साप्ताहिक

RNI-MPHIN/2015/72544

जागत गांव हमार

पंचायत की विकास गाथा, सरकार तक

चौपाल से भोपाल तक

भोपाल, सोमवार 26 दिसंबर -01 जनवरी, 2023 वर्ष-8, अंक-37 | भोपाल, इंदौर, उज्जैन, सागर, मुरैना, रीवा, शिवपुरी से एक साथ प्रकाशित | पृष्ठ :-8, मूल्य :- 2 रुपए

साक्षात्कार: आईसीएआर अटारी जोन-9 के निदेशक ने कहा-कृषि के लिए जरूरी है सही सोच और वैज्ञानिकता

पुराना ढर्रा छोड़ें तो 5 एकड़ का काश्तकार 5 को दे सकता है रोजगार

भोपाल। जागत गांव हमार

पुराना ढर्रा यदि छोड़ दे तो देश में खेती करने वाला 5 एकड़ का छोटा काश्तकार भी 5 व्यक्तियों को रोजगार दे सकता है। लेकिन इसके लिए जरूरी है, सही सोच और वैज्ञानिकता। यह बात भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद अटारी जोन-9 के निदेशक एसआरके सिंह ने **जागत गांव हमार** से खास चर्चा के दौरान कही। खाद्यान्न में समृद्ध भारत में विज्ञान आधारित कृषि को बढ़ावा देने संबधी कृषि विज्ञान केंद्र के प्रयासों की सराहना करते हुए किसानों को कृषि में तकनीकि के इस्तेमाल की जरूरत अनिवार्य मानते हैं। जबलपुर स्थित अटारी जोन के माध्यम से कृषि अनुसंधान परिषद 54 कृषि विज्ञान केंद्रों और स्वयं सेवी संस्थाओं के सहयोग से मप्र और छग के किसानों के बीच वैज्ञानिक जागरूकता बढ़ाने में जुटी है। उनका कहना है थ्क समय बदलने के बाद भी हमारे यहां व्यवहारिक संचार का अभाव है। जबकि किसान, उपभोक्ता और व्यापारी को परम्परागत ढर्रे को छोड़कर न केवल मानसिकता बदलने, बल्कि तकनीकि का इस्तेमाल की जरूरत है। इसलिए जागरूकता कार्यक्रम संस्थान चला रहा है। क्रियान्वयन की शुरुआत करने के लिए लोगों को आगे आना होगा। क्योंकि यह समय खेती का तरीका बदलने का है। परम्परागत तरीके से खेती कर रहे किसानों को समझने की जरूरत है। देश का युवा आईटी छोड़कर हवा में खेती करने आ रहे हैं। वह 5 लाख रुपए तक कमा रहा है।

सभी के लिए योजनाएं | एक साथ यदि रासायनिक उत्पादों को बंद कर दिया गया तो खाद्यान की उत्पादकता पर इसका विपरीत असर पड़ेगा। वहीं छोटी जोत के बजाय सरकार द्वारा बनाई जाने वाली योजनाएं बड़े किसानों के लिए होती हैं के संबंधी आम आदमी के सवाल पर वे कहते हैं कि सरकार की योजना सभी के लिए हैं।

हमें मिला विकल्प वैसे भी अब स्पष्ट हो गया है कि यदि कोई व्यक्ति 2 से 5 एकड़ तक की भूमि में खेती के साथ सारे तरह पालन मसलन बागवानी, मात्स्यिकी और पशु पालन भी करता है तो वह 5 व्यक्तियों को रोजगार भी दे सकता है। इसमें ज्यादा खर्च भी नहीं है सिर्फ एक का कचरा दूसरे को इस्तेमाल के लिए देना है। सरकार द्वारा जैविक व प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने संबंधित नीति के बीच रासायनिक उत्पादों की दिनों दिन बढ़ती मांग के सवाल पर बताते हैं कि हमें यह विकल्प मिला है। अब यह तय कर सकते है कि फसल का उद्देश्य व्यापारिक है या स्वयं के लिए है।

छोटे-बड़े किसानों को लेकर कोई भेद नहीं

छोटे-बड़े किसानों को लेकर कोई भेद नहीं है। लेकिन यह बात जरूर है कि फायदा सिर्फ बड़े किसान ले पाते हैं। क्योंकि उनको इसके फायदे पता हैं। जबकि छोटा किसान जोखिम नहीं उठाना चाहता है। सरकार के मिलट मिशन को लेकर उनका कहना है कि कि खाद्यान्न सक्षमता के बाद अब सेहत की बारी है। इसका लक्ष्य पोषण के पारंपरिक ज्ञान और अनुभव से समाज को जागरुक कराना है।

प्रदेश की शिवराज सरकार फसल चक्र की समय सीमा भी बढ़ाएगी

प्रदेश में किसानों को कर्ज चुकाने मिलेगा दोगुना समय

भोपाल। जागत गांव हमार

नए साल के पहले मध्यप्रदेश में अब किसानों को कर्ज चुकाने के लिए दोगुना समय मिल सकता है। दरअसल, शिवराज सरकार फसल चक्र की समय सीमा बढ़ाने जा रही है। इसके तहत अल्पावधि में पकने वाली फसलों गेहूं, चना, धान आदि के लिए यह फसल चक्र या क्रॉप सीजन 12 माह का होगा, जबकि लंबी अवधि में पकने वाली गन्ने और केले की फसल के लिए सीमा 18 माह तय होगी। अभी तक अल्पावधि फसलों के लिए फसल चक्र 4-6 और लंबी अवधि की फसलों के लिए 8-9 माह होता है। मप्र में बैंक किसानों को अल्प कालीन फसलों के लिए कर्ज चुकाने के लिए दो फसल चक्र और लंबी अवधि की फसलों के लिए एक फसल चक्र की मोहलत देती है। इसके बाद कर्ज की राशि डूबत खातों या एनपीए में डाल देते हैं।

मध्यप्रदेश में डिफॉल्टर किसानों की संख्या घटेगी। अब उपज का 12-18 माह का होगा फसल चक्र।

30 लाख डिफाल्टर

- मप्र में कुल 1 करोड़ किसान हैं। इनमें से करीब 30 लाख डिफॉल्टर हैं।
- फसल चक्र के आधार पर मिलता है। किसानों को कर्ज चुकाने के लिए समय ज्यादा मिलेगा।

इस तरह बढ़ा एनपीए

	सितं-19	सितं-20	सितं-22
कृषि ऋण	15,539	18,256	19,976

-राशि करोड़ रुपए में।

नई व्यवस्था से मप्र में डिफॉल्टर किसानों की संख्या में बढ़ोतरी की वर्तमान दर आधी रह जाएगी। किसानों को कर्ज चुकाने के लिए ज्यादा समय मिलेगा। अभी राज्य में करीब 30 लाख किसान डिफॉल्टर हैं।

-तरसेम सिंह जीरा, समन्वयक, एसएलबीसी

साहूकारों से भी मिलेगा छुटकारा

किसान को अगली फसल के लिए बैंक कर्ज नहीं देते। सोसायटियों से क्रेडिट पर खाद-बीज नहीं मिलता। मजबूरन किसानों को साहूकारों से कर्ज लेकर नकद में खाद-बीज खरीदना पड़ता है। प्रदेश में कहीं फसल जल्दी पकती है, कहीं विलंब से।

अच्छा भाव भी मिलेगा

किसानों की शिकायत रहती है कि बैंक फसल कटने के बाद उसे उचित मूल्य पर बेचने तक का समय नहीं देते। सस्ते दामों में उपज बेचकर बैंकों का कर्ज चुकाना पड़ता है। यह न करने पर किसान डिफॉल्टर हो जाते हैं। लेकिन एक अब फसल चक्र की गणना होगी। इससे अच्छे भाव का इंतजार करने का समय मिलेगा।

पिछली बार पांच राज्यों में भोपाल था नंबर-वन

नए साल में ओडीएफ+ होंगे भोपाल के 144 गांव

भोपाल। जागत गांव हमार

शहरों के साथ मध्यप्रदेश के गांव भी सफाई में इतिहास रच रहे हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण (ग्रामीण)-2022 के नतीजों में 5 स्टेट में भोपाल नंबर-1 पर रहा था। यानी, भोपाल के गांव सबसे स्वच्छ थे। जिले के गांव यह रिकॉर्ड फिर से दोहरा सकते हैं। अगले सर्वेक्षण को लेकर शुरुआत भी कर दी गई है। जनवरी में सर्वेक्षण की टीम भोपाल आ सकती है। इसलिए बाकी बचे गांवों को ओडीएफ+ किया जा रहा है। दावा है कि जनवरी में 144 गांव ओडीएफ प्लस कर दिए जाएंगे। यानी, ये गांव पूरी तरह से खुले में शौच मुक्त हो जाएंगे और वहां कम से कम एक सामुदायिक शौचालय हो। भोपाल की 222 ग्राम पंचायतों में कुल 469 गांव शामिल हैं। इनमें से 325 गांव इस साल ओडीएफ प्लस हो चुके हैं। बाकी बचे 144 गांवों को लेकर पंचायत स्तर पर तैयारियां की जा रही है।

जनवरी में आएगी टीम

स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण-2023 में तीन टीमें आएंगी। पहली टीम जनवरी में आएगी, जो दस्तावेजों की जांच करेगी। इसके बाद मैदानी टीम भी आएगी। पिछले सर्वेक्षण में वेस्ट जोन में शामिल स्टेट में मप्र में की पोजिशन एक नंबर थी। इनमें भोपाल अव्वल रहा था। वेस्ट जोन में मप्र, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और गोवा शामिल थे।

इनका कहना है

जनवरी में पूरे जिले को ओडीएफ प्लस घोषित कर देंगे। ताकि, सर्वेक्षण में इनके अंक भी मिल सके। जहां कचरे की छंटाई के बाद उसे बेच रहे हैं। गांवों में 45 हजार मीटर नालियों का निर्माण किया गया है। जिनसे गंदा पानी नालियों के जरिए निकल रहा है। स्वच्छता के पक्के स्ट्रेक्चर भी बना रहे हैं। दो हजार स्ट्रेक्चर बन चुके हैं, जबकि 500 बनाए जा रहे हैं।

ऋतुराज, सीईओ, जिपं, भोपाल

1071 लघु वनोपज समिति प्रबंधकों का बढ़ाया वेतन, प्रदेश के वन बनेंगे पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र

वन उत्पाद, कलात्मक वस्तुओं और पौष्टिक व्यंजनों से सजाए गए स्टॉल

40 लाख तेंदूपत्ता संग्राहकों की बंद सुविधाएं फिर बहाल

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश के वनवासी को वनों के उत्पाद से अधिकाधिक लाभ दिलवाने के लिए अनेक निर्णय लिए गए हैं। इस कड़ी में वन मेला भी वनोपज उत्पादकों की आय वृद्धि का प्रमुख माध्यम है। वन्य-प्राणी संरक्षण के क्षेत्र में प्रदेश विशेष पहचान बना रहा है। वनों से वनवासियों को आर्थिक समृद्धि दिलाने के उद्देश्य से भी फैसले लिए गए हैं। मुख्यमंत्री भोपाल के लाल परेड मैदान में सात दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय वन मेले के शुभारंभ कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने

कहा कि मप्र में वनोपज से स्थानीय वनवासियों को लाभ दिलवाने की पुख्ता व्यवस्था की गई है। न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित होने से तेंदूपत्ता संग्राहकों को हानि नहीं होती। तेंदूपत्ता संग्रहण का कार्य पेसा विकासखण्डों में पंचायतों के माध्यम से हो सकेगा। वर्ष 2017 और 2018 में तेंदूपत्ता श्रमिकों को पानी की कुप्पी, साड़ी और चप्पल आदि सामग्री प्रदाय की गई थी। वर्ष 2019 में तत्कालीन सरकार ने तेंदूपत्ता संग्राहकों को ये सुविधाएं देना बंद कर दी। राज्य सरकार इस वर्ष से 40 लाख तेंदूपत्ता संग्राहकों को यह सामग्री फिर से प्रदान करेगी।

1071 प्रबंधकों की संख्या | मुख्यमंत्री ने कहा कि लघु वनोपज समिति प्रबंधकों की भूमिका महत्वपूर्ण और सराहनीय है। इनका मानदेय वर्ष 2016 में 5 हजार रुपए था, जो 6 हजार किया गया था। इसे बढ़ा कर 10 हजार रुपए तक लाने का कार्य हुआ। अब इसमें पुन: वृद्धि कर 13 हजार मासिक किया जाएगा। प्रदेश में समिति प्रबंधकों की संख्या 1071 है।

-केंद्र सरकार से नहीं बढ़ा राज्य अनाज का आवंटन

-केंद्र सरकार नहीं बढ़ा अन का आवंटन

मध्य प्रदेश में अब मुफ्त का नहीं मिलेगा गेहूं!

भोपाल। जागत गांव हमार

मध्य प्रदेश के गरीब परिवारों को मुफ्त के गेहूं की रोटी मिलेगी, यह तय नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि मप्र के दो बार मांग करने के बावजूद केंद्र ने अब तक गेहूं का आवंटन नहीं बढ़ाया है। इसकी वजह से भोपाल समेत 20 जिलों के लाखों गरीब परिवारों को मुफ्त में मिलने वाले गेहूं का वितरण पांच माह से बंद है। यह गेहूं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्ना योजना (पीएमजीकेएवाई) के तहत सार्वजनिक वितरण प्रणाली की उचित मूल्य राशन दुकानों से मिलता था। अभी गेहूं की जगह पांच किलो चावल दिया जा रहा है। इस योजना का विस्तार 31 दिसंबर तक ही है। प्रदेश के सभी जिलों में पूर्व से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत गरीबों को दो रुपए प्रति किलो की दर पर प्रति माह प्रति सदस्य पांच किलो गेहूं मिलता है। जबकि (पीएमजीकेएवाई) के तहत प्रति माह प्रति सदस्य पांच किलो नि:शुल्क अनाज देने की व्यवस्था थी, जिसमें चार किलो गेहूं व एक किलो चावल दिया जाता था। अब इसमें केवल चावल मिल रहा है। वितरण प्रणाली से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि केंद्र से ही आवंटन रोका गया है, जिसे शुरू कराने की कोशिश की गई। लेकिन अब तक आवंटन नहीं मिला है।

फैक्ट फाइल

- एक करोड़ 21 लाख 47 हजार 43 है राशन कार्डधारी
- प्रदेश में 26 हजार 299 राशन दुकानें
- 3.50 लाख टन प्रति माह चावल का वितरण
- 1.50 लाख टन गेहूं का प्रति माह वितरण

इन जिलों में वितरण बंद

प्रदेश के जिन जिलों में नि:शुल्क गेहूं वितरण बंद हुआ है, उनमें भोपाल, बैतूल, छिंदवाड़ा, जबलपुर, कटनी, नर्मदापुरम, नरसिंहपुर, पन्ना, रायसेन, रीवा, सतना, सिवनी, सीधी, सिंगरौली शामिल हैं। इन जिलों में पीएमजीकेएवाई के तहत गेहूं वितरित किया जा रहा था। अब यहां उक्त योजना के तहत केवल चावल ही दिया जा रहा है।

इन जिलों में दो योजना

छह जिले अनूपपुर, बालाघाट, डिंडोरी, मंडला, शहडोल और उमरिया में पीएमजीकेएवाई और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम योजना चल रही है। दोनों के तहत गेहूं का वितरण होता है, लेकिन यहां भी सिर्फ चावल ही बांटा जा रहा है।

यह बताई जा रही वजह

- जिन जिलों में गेहूं का आवंटन रोका गया है, वहां के ज्यादातर लोग भोजन में चावल अधिक पसंद करते हैं।
- धान का उत्पादन भी बंपर हुआ है और खरीदी भी अच्छी हुई है, इसलिए चावल की खपत बढ़ाने की मंशा है।

इन जिलों में यह स्थिति

- **भोपाल:** तीन लाख 64 हजार परिवारों के 15 लाख सदस्यों का राशन प्रभावित हुआ है। इन्हें पीएमजीकेएवाई योजना के तहत गेहूं बंद कर चावल ही दिया जा रहा है।
- **इंदौर:** पीएमजीकेएवाई व एनएफएसए योजना के तहत तीन किलो चावल और दो किलो गेहूं बांटा जा रहा है।
- **ग्वालियर:** एनएफएसए में दो किलो गेहूं, तीन किलो चावल दिया जा रहा है। पीएमजीकेएवाई में चार किलो चावल और एक किलो गेहूं वितरित किया जा रहा है।

केंद्र स्तर से राशन वितरण की व्यवस्था में बदलाव किया गया था, जिसके कारण पीएमजीकेएवाई के तहत गेहूं की जगह चावल बांटा जा रहा है। केंद्र को गेहूं का आवंटन करने के लिए दो बार पत्र लिख चुके हैं। आगे भी प्रयास करेंगे, लेकिन आवंटन मिलेगा यह अभी तक तय नहीं है।

दीपक सक्सेना, संचालक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

लाल परेड मैदान में उमड़ रहा जन सैलाब

वन मेला में दो दिन में 13 लाख रु. के बिके उत्पाद

भोपाल। भोपाल के लाल परेड ग्राउंड पर अंतर्राष्ट्रीय वन मेले के प्रति आमजन का आकर्षण दिनों दिन परवान चढ़ने लगा है। दूसरे दिन तक लोगों ने 13 लाख रुपए के वनोपज और हर्बल उत्पाद से निर्मित औषधियां खरीदीं। मप्र राज्य लघु वनोपज संघ के एडिशनल एमडी विभाष कुमार ठाकुर ने बताया कि वन मेला में संचालित ओपीडी में 4 हजार से ज्यादा आगंतुकों ने नि:शुल्क चिकित्सीय परामर्श प्राप्त किया। चिकित्सकीय परामर्श के लिए वन मेले में सुबह के समय 63 और शाम के समय 62 आयुर्वेद चिकित्सक और अनुभवी वैध अपनी सेवाएं दे रहे हैं। लघु वनोपज प्र-संस्करण और अनुसंधान केन्द्र भोपाल के विंध्य हर्बल्स ब्रांड के उत्पाद शहद, च्यवनप्राश और त्रिकुट को उनके प्रभावी असर और गुणवत्ता में अव्वल होने की वजह से मेले में आने वाले लोगों में खरीदी के लिए भीड़ लग रही है। मेले में नर्सरी के औषधीय पौधे खरीदने के लिए लोगों का जमावड़ा लग रहा है।

महुए का अचार

प्रधानमंत्री वन-धन योजना में प्रदेश और अन्य राज्यों में संचालित वन-धन केन्द्रों में बनाए जा रहे महुए, देशी मोटे अनाज के प्रति बढ़ती लोकप्रियता ने देशी महुए के लड्डू, महुए का अचार, महुआ कुकीज, कोदो-कुटकी कुकीज, अलसी लड्डू, तिल लड्डू, देशी मक्का कुकीज, आंवला कैंडी और आंवला पाचक जैसे उत्पाद लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं।

कृषि आधारित व्यवसायों पर दी जानकारी

55 छात्रों को प्राकृतिक खेती का पढ़ाया पाठ

टीकमगढ़।

कृषि विज्ञान केंद्र टीकमगढ़ में शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बम्होरीकला टीकमगढ़ के 55 छात्रों को डॉ. बीएस किरार, प्रधान वैज्ञानिक एवं प्रमुख द्वारा प्राकृतिक खेती एवं कृषि आधारित व्यवसायों पर जानकारी दी गई। छात्रों को रासायनिक खेती के स्वास्थ्य, भूमि, जल एवं वायु पर पड़ने वाले दुष्परिणामों के बारे में बताया गया और प्राकृतिक खेती के फायदों से अवगत कराया गया। प्राकृतिक खेती के अन्तर्गत हमें पोषक तत्वों एवं नींदा प्रबंधन के लिए बाजार से कोई सामग्री खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ती। यह कम लागत की खेती है। वर्तमान में मानव समुदाय में बढ़ रही बीमारियों के रोकथाम में भी सहायक है। छात्रों को कृषि आधारित व्यवसायों जैसे-दुग्धोत्पादन के लिए पशुपालन, बकरीपालन, मुर्गीपालन, मछलीपालन एवं उच्च तकनीक से सब्जीत्पादन के बारे में विस्तार से बताया गया। इन सभी उद्यमों के लिए राज्य शासन द्वारा बहुत सी कृषक कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनका फायदा उठाकर कृषि आधारित व्यवसाय शुरू कर सकते हैं।

गृह वाटिका का बताया उपयोग

छात्रों को परिवार के लिए पोषण वाटिका/गृह वाटिका का महत्व एवं उपयोगिता भी समझाई गई। बताया गया कि छात्र अपनी पढ़ाई के दौरान प्रतिदिन 1 घंटे का समय अपनी पोषण वाटिका में देने से परिवार को रसायन मुक्त सब्जियां एवं फल खिला सकते हैं। परिवार का सब्जियों पर होने वाले खर्च को कम करके उस राशि को अपनी पढ़ाई पर खर्च कर सकते हैं। सभी छात्रों को कृषि विज्ञान केंद्र की प्रदर्शन इकाइयों का भी भ्रमण कराया गया।

देश में पशु प्रजनन फार्मों और साइलेज बनाने वाली इकाइयों को मिलेगी सब्सिडी

भोपाल। केन्द्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री संजीव बालियान ने कहा कि हमारा विभाग 50 लाख से अधिक किसानों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार देगा। राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत गाय/भैंस/सूअर/मुर्गी/बकरी प्रजनन फार्म और हरा चारा सुरक्षित रखने वाली (साइलेज) इकाइयों को क्रमश: 4 करोड़, 1 करोड़, 60 लाख, 50 लाख रुपये की सब्सिडी देने की योजना है। कुल राशि में से 50 प्रतिशत सब्सिडी भारत सरकार द्वारा दी जाएगी। इसके अलावा, ऋण राशि पर 3 प्रतिशत ब्याज अनुदान भी एचआईडीएफ योजना के तहत लिया जा सकता है। पशुओं के इलाज के लिए 4332 से अधिक चल पशु चिकित्सा इकाई खोलने की व्यवस्था की जा रही है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत देशी गाय की नस्लों के पालन-पोषण को प्रोत्साहित किया जा रहा है। कुल 90598 नौकरियों में से, 16000 युवाओं को मैत्री योजना के तहत रोजगार मिला है। देश के युवाओं को मंत्रालय की योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए ऑनलाइन सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है।

- केंद्रीय मंत्री बोले- देश में 4332 चल पशु चिकित्सा इकाई खोलेगी सरकार
- 90598 नौकरियों में से,16000 युवाओं को मैत्री योजना से मिला रोजगार

-किसानों ने की चर्चा और शंका का समाधान

रीवा में उद्यमी किसानों को कृषि स्टार्टअप का बताया महत्व

रीवा। कृषि विज्ञान केंद्र रीवा द्वारा भारत सरकार की कृषि से संबंधित स्टार्ट अप कार्यक्रम से उद्यमी कृषकों को जोड़ने के लिए जवाहर लाल नेहरू कृषि विवि जबलपुर के एग्री बिजनेस प्रबंधन संस्थान की टीम डॉ. हेमंत राहंगडाले एवं अन्य ने विस्तृत ढंग से कृषि स्टार्टअप एवम जवाहर एग्री बिजनेस इनक्यूबेटर के विषय में जानकारी देते हुए इस योजना से प्रेरणा एवं साकार स्कीम के अंतर्गत आवेदन एवम लाभ होने पर चर्चा की। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित प्रत्येक कृषक उद्यमी ने अपने नवाचार एवं भावी स्टार्टअप प्रस्ताव के विषय पर गहन चर्चा की। साथी अपनी शंका का समाधान किया। इस कार्यक्रम में कृषि विज्ञान केंद्र रीवा के प्रमुख डॉ. एके पांडेय, प्रधान वैज्ञानिक डॉ. आरपी जोशी, डॉ. राजेश सिंह, डॉ. अखिलेश कुमार, डॉ. संजय सिंह ने अपने उपयोगी विचार व सुझाव दिए।

इनका रहा योगदान

कार्यक्रम के संयोजक डॉ. सीजे सिंह, कार्यक्रम का संचालन डॉ. संजय सिंह, आभार प्रदर्शन डॉ. अखिलेश कुमार ने किया। केंद्र के वैज्ञानिक डॉ. स्मिता सिंह, डॉ. केएस बघेल, डॉ. मधुलिका लघु धान्य परियोजना, मंजू शुक्ला सहित 23 उद्यमी कृषकों की उपस्थिति ने कार्यक्रम को सफल बनाने में विशेष योगदान दिया।

वृहद परियोजना नियंत्रण मंडल की बैठक में सीएम ने कहा

सिंचाई परियोजनाओं को तय समय में करो पूरा

» 748 करोड़ 57 लाख की 6 वृहद सिंचाई परियोजनाएं मंजूर

» पूरा होने से 38 हजार 470 हेक्टेयर क्षेत्र में होगी सिंचाई

भोपाल। जागत गांव हमार

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में सिंचाई के लिए निर्मित होने वाली वृहद परियोजनाओं का कार्य तय समय-सीमा में और गुणवत्तापूर्ण किया जाए। मुख्यमंत्री ने जल संसाधन विभाग की 6 वृहद सिंचाई परियोजनाओं की स्वीकृति की अनुशंसा की। इन परियोजनाओं के पूरा होने से 38 हजार 470 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता में वृद्धि हो सकेगी। परियोजनाओं के पूरा होने की अनुमानित लागत 748 करोड़ 57 लाख रुपए है। मुख्यमंत्री वृहद परियोजना नियंत्रण मंडल की 117 वीं बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट, वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा, कृषि मंत्री कमल पटेल, नर्मदा घाटी विकास राज्य मंत्री भारत सिंह कुशवाह, अपर मुख्य सचिव एसएन मिश्रा और संबंधित विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।

हरबाखेड़ी बैराज मध्यम परियोजना

उज्जैन जिले की महिदपुर तहसील में क्षिप्रा नदी पर प्रस्तावित हरबाखेड़ी बैराज मध्यम परियोजना स्वीकृत की गई। यह परियोजना माइक्रो सिंचाई पद्धति पर आधारित है। परियोजना की अनुमानित लागत 104 करोड़ 28 लाख है। परियोजना में 10.76 एमसीएम के बैराज तथा दाब युक्त पाइप नहर निर्माण का कार्य शामिल है। परियोजना के पूरा होने से महिदपुर तहसील में 3050 हेक्टेयर क्षेत्र में रबी फसलों की सिंचाई हो सकेगी।

पांगरी माइक्रो सिंचाई परियोजना

बुरहानपुर जिले की खकनार तहसील में बड़ी उतावली नदी पर प्रस्तावित पांगरी मध्यम माइक्रो सिंचाई परियोजना को स्वीकृति दी गई। इस परियोजना की अनुमानित लागत 112 करोड़ 50 लाख है। परियोजना के पूरा होने से बुरहानपुर जिले की खकनार तहसील के 10 ग्रामों में 4400 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो सकेगी।

लामटा नेटवर्क परियोजना लामटा नेटवर्क परियोजना

बालाघाट जिले के परसवाड़ा विकासखंड में प्रस्तावित लामटा प्रेशराइज्ड पाइप इरिगेशन नेटवर्क परियोजना को स्वीकृति दी गई। परियोजना में लगभग 100 वर्ष पूर्व निर्मित क्षतिग्रस्त हिस्से की अपस्ट्रीम में पम्प हाउस का निर्माण कर हॉज सिस्टम से 55 ग्रामों की 9,630 हेक्टेयर भूमि पर खरीफ (धान) की फसल में सिंचाई की जा सकेगी। परियोजना की लागत 137 करोड़ 26 लाख है।

जैरा सिंचाई परियोजना

सागर जिले की जैरा मध्यम माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना को स्वीकृति दी गई। इसकी अनुमानित लागत 102 करोड़ 52 लाख रुपए है। इससे 5400 हेक्टेयर में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी। इसमें बांध निर्माण, प्रेशराइज्ड पाईप इरिगेशन प्रणाली का कार्य किया जाएगा।

सामाकोटा सिंचाई परियोजना

उज्जैन जिले की सामाकोटा बैराज सिंचाई परियोजना को स्वीकृति दी गई। इसकी अनुमानित लागत 141 करोड़ 11 लाख है। इससे लगभग 6 हजार हेक्टेयर में सिंचाई हो सकेगी। इसके अंतर्गत बैराज निर्माण, प्रेशराइज्ड पाईप इरिगेशन प्रणाली विकास कार्य शामिल हैं।

टेम सिंचाई परियोजना

विदिशा जिले की टेम मध्यम सिंचाई परियोजना को भी स्वीकृति दी गई। इस परियोजना में बांध निर्माण का कार्य प्रारंभ किया जा चुका है। परियोजना में बाँध निर्माण तथा प्रेशराइज्ड पाइप नहर निर्माण का कार्य शामिल है। परियोजना की अनुमानित लागत 151 करोड़ 28 लाख है। परियोजना से भोपाल जिले की बेरसिया तहसील एवं गुना जिले की मकसूदनगढ़ तहसील के 47 ग्रामों के 9,990 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो सकेगी।

अब गौशालाओ से गोबर और गौ-मूत्र मिलेगा

गौ-एप का हुआ डेमो, गौ-मूत्र से बनाई हाइड्रोजन

गाय संरक्षण की अनोखी पहल

भोपाल। जागत गांव हमार

भारतीय संस्कृति में गाय का बहुत महत्व है परंतु आज के समय में गाय को बेसहारा छोड़ दिया जाता है। ऐसे में गोवंश के संरक्षण के लिए कई पहल की जा रही है। ऐसी ही एक पहल डॉ.एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय (एकेटीयू) में की गई है। एकेटीयू में गौ-एप और गौ-मूत्र से हाइड्रोजन और फिर बिजली बनाने का डेमो दिया गया।

इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने एप को अपने मोबाइल में डाउनलोड भी किया। साथ ही परिसर में मौजूद एक गाय का चेहरा एप में फीड कर खुद डेमो किया। आने वाले दिनों में यह एप गायों को पहचान देगा। एस एप में गायों की पूरी कुंडली रहेगी। वहीं गो-मूत्र का इस्तेमाल हाइड्रोजन बनाने में किया जा सकेगा।

एकेटीयू के कुलपति प्रो. प्रदीप कुमार मिश्र ने बताया कि गायों का पूरा ब्योरा इस एप में दर्ज होगा। साथ ही एप के जरिए दान दाताओं को जोड़ा जाएगा। जो एनजीओ के जरिए गौशालाओं को दान करेंगे। एप से पता चलेगा कि उनका पैसा सही जगह लगा है या नहीं। साथ ही गायों की सेहत भी उन्हें पता चलती रहेगी। साथ ही एनजीओ को गौशालाओ से गोबर और गौ-मूत्र मिलेगा। वो खाद और अन्य चीजें बना सकेंगे। एप से जन साधारण भी जुड़ सकेंगे।

गाय की होगी कुंडली

इंडियन बायोगैस एसोसिएशन के सहयोग से टेक मशीनरी लैब के निशांत कृष्णा और उनकी टीम से मिलकर गौ एप बनाया है। फेस बायोमेट्रिक की तरह गौ-वंश के चेहरे से उनकी पहचान एप के जरिए होगी। इस एप में गो वंश की पूरी डीटेल रहेगी।साथ ही एप में गायों को दान देने वालों को भी जोड़ा जाएगा।

गायों के लिए एप सहारा

इस पहल से न केवल गाय बेसहारा होने से बचेंगी बल्कि उनसे फायदा भी होगा। गौशालाओं से गोबर और मूत्र लेकर बायोगैस, खाद, अगरबत्ती समेत अन्य चीजें बनेगी। इस माडल के प्रयोग से गौशालाओं से निकलने वाले गोबर से खाद बनेगी तो मूत्र से आयुर्वेदिक दवा बनाने के साथ बायो हाइड्रोजन बनाने का भी प्रयास हो रहे हैं। इसका फायदा पर्यावरण को होगा।

पशुओं को नहीं छोड़ पाएंगे बेसहारा

इस एप का एक फायदा ये भी होगा कि लोग अपने पालतू जानवरों को बेसहारा नहीं छोड़ पाएंगे। क्योंकि इस एप में पशुओं का पूरा ब्योरा फोटो के साथ डालने की सुविधा होगी। इसके बाद दोबारा एप पर पशुओं की फोटो डालने पर पता चल जाएगा कि उक्त पशु का मालिक कौन है। गाय आधारित उन्नति यानी गौ एप को कुलपति प्रो.प्रदीप कुमार मिश्र और आईआईएम अहमदाबाद के प्रो.अमित गर्ग के मार्गदर्शन में इंडियन बायोगैस एसोसिएशन व टेक मशीनरी लैब ने मिलकर बनाया है।

पिछले वर्ष की तुलना में 2 लाख हेक्टेयर ज्यादा बोवनी

मध्य प्रदेश में 90 फीसदी बोवनी

भोपाल। जागत गांव हमार

चालू रबी सीजन में फसलों की बोवनी गत वर्ष से अधिक हो गई है। इस वर्ष राज्य में गेहूं का रकबा कम कर दलहनी एवं तिलहनी फसलों का रकबा बढ़ाने पर जोर दिया गया है। 16 दिसम्बर तक 125.72 लाख हेक्टेयर में बोवनी हुई है, जो लक्ष्य के विरुद्ध लगभग 90.4 फीसदी है। गत वर्ष इस अवधि में 121.18 लाख हेक्टेयर में बोनी हुई थी। वहीं गेहूं की बोवनी में तेजी आई है। अब तक गत वर्ष की तुलना में लगभग 2 लाख हेक्टेयर अधिक क्षेत्र में बोवनी हो गई है। कृषि विभाग के मुताबिक प्रदेश में रबी फसलों का सामान्य क्षेत्र 124 लाख 77 हजार हेक्टेयर है। इस वर्ष 139.06 लाख हेक्टेयर में रबी फसलें लेने का लक्ष्य रखा गया है। कृषि विभाग के अनुसार अब तक 125.72 लाख हेक्टेयर में बोवनी कर ली गई है। इसमें राज्य की प्रमुख रबी फसल गेहूं की बोनी 80.32 लाख हेक्टेयर में हुई है। जबकि गत वर्ष अब तक 78.62 लाख हेक्टेयर में गेहूं बोया गया था। इस प्रकार लगभग 2 लाख हेक्टेयर में गेहूं की बोवनी अधिक हुई है।

प्रदेश में रबी फसलों की बोवनी

16 दिसम्बर 2022 तक (लाख हेक्टेयर में)

फसल	लक्ष्य	बोवनी
गेहूं	89.03	80.32
जौ	0.52	0.53
चना	24.47	20.3
मटर	2.8	2.47
मसूर	6.49	6.44
सरसों	13.07	13.8
अलसी	1.27	1.16
गन्ना	1.4	0.7

स्रोतः कृषि विभाग, मप्र

1.40 लाख हेक्टेयर में गन्ना

वहीं गत वर्ष अब तक सरसों 7.74 लाख हेक्टेयर में बोई गई थी। अलसी की बोवनी 1.16 लाख हेक्टेयर में हुई है। इस वर्ष गन्ना 1.40 लाख हेक्टेयर में लिया जाएगा। अब तक इसकी बोवनी 70 हजार हेक्टेयर में हुई है, जबकि गत वर्ष इस अवधि में 82 हजार हेक्टेयर में गन्ना बोया गया था। इस प्रकार राज्य में अब तक कुल अनाज फसलें 80.85 लाख हेक्टेयर में, दलहनी फसलें 29.21 लाख हेक्टेयर में एवं तिलहनी फसलें 14.96 लाख हेक्टेयर में बोई गई हैं।

चना का घट गया रकबा

राज्य की दूसरी प्रमुख फसल चने की बोनी अब तक 20.30 लाख हेक्टेयर में हो गई है जो गत वर्ष समान अवधि में 24.84 लाख हेक्टेयर में हुई थी। चने की बुवाई में लगभग चार लाख हेक्टेयर की कमी आई है। अन्य फसलों में अब तक मटर 2.47 लाख हेक्टेयर में, मसूर 6.44 लाख हेक्टेयर में बोई गई है। राज्य की प्रमुख तिलहनी फसल सरसों की बोनी लक्ष्य से अधिक 13.80 लाख हेक्टेयर में हुई है। जबकि लक्ष्य 13.07 लाख हेक्टेयर रखा गया है।

घोड़े खड़े होकर झपकी लेते हैं, जानिए इसका कारण

» डॉ. योगिता पाण्डेय
» डॉ. डॉ. अखिलेश पाण्डेय
» डॉ. सुनील कुमार गुप्ता
» डॉ. डॉ अलका सुमन
-पशु चिकित्सा महाविद्यालय, महू (म.प्र.)

घोड़े अपने जीवन का अधिकांश समय खड़े रहते हैं, और माना जाता है कि वे मांसपेशियों के प्रयास के बिना अपने अंगों को सीधा रखने में सक्षम होते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि घोड़े वास्तव में अपने पैरों पर सोते हैं। तो, सवाल यह है कि घोड़े खड़े होकर झपकी क्यों लेते हैं? मुख्य रूप से क्योंकि लेटते समय सोना खतरनाक हो सकता है, घोड़ों को उठने में थोड़ा समय लगता है, जो उन्हें शिकारियों के हमलों के प्रति संवेदनशील बनाता है। घोड़ा आराम कर सकता है और गिरने की चिंता किए बिना झपकी ले सकता है। जब घोड़ों को गहरी नींद की आवश्यकता होती है, वे आमतौर पर छोटे अंतराल की एक श्रृंखला के लिए लेट जाते हैं, जो दिन में लगभग दो से तीन घंटे तक होता है।

एक घोड़ा लंबे समय तक लेट नहीं सकता है। अगर कोई बहुत देर तक नीचे लेटता है तो यह घातक हो सकता है। एक घोड़ा 500 किगा से भी ज्यादा वजन का हो सकता है, जिसके कारण होने वाला दबाव मांसपेशियों और तंत्रिकाओं को नुकसान पहुंचा सकता है और घोड़े के लिए सांस लेना या रक्त को ठीक से प्रसारित करना मुश्किल बना देता है। हाँ, घोड़ों को खड़े होने पर हल्की झपकी आती है शोधकर्ताओं का अनुमान है कि घोड़े दिन में 5-7 घंटे आराम करते हैं और बहुत कम ऊर्जा के साथ अपना संतुलन बनाए रखने के लिए मांसपेशियों, स्नायुबंधन, टेंडन और जोड़ों के संयोजन का उपयोग करके हल्की नींद में खड़े होकर सो सकते हैं। घोड़ों का सबसे दिलचस्प हिस्सा यह है कि वे इसे कैसे करते हैं। घोड़ों में मांसपेशियों और मांसपेशियों और हड्डियों को आपस में जोड़ने वाले हिस्सों (स्नायुबंधन और कण्डरा) की एक विशेष व्यवस्था होती है। इसे स्टे उपकरण कहा जाता है। वे स्टे उपकरण के माध्यम से ऐसा करने में सक्षम हैं, यह घोड़े के कंधे पर ताला लगाकर और उसके पिछले हिस्से को स्थिर करके काम करता है। टेंडन और स्नायुबंधन की एक विशेष प्रणाली जो घोड़े को अपने पैरों में प्रमुख जोड़ों को बंद करने में सक्षम बनाती है। उपकरण का मतलब है कि घोड़े तीन पैरों पर खड़े हो सकते हैं और दूसरे पैर को आराम दे सकते हैं। वे जिस पैर को आराम देते हैं उसे बदल सकते हैं ताकि उनके सभी पैरों को ब्रेक लेने का मौका मिले।

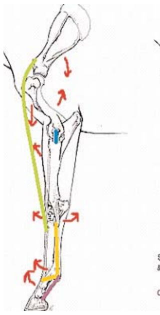

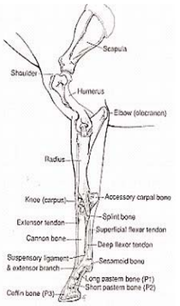

स्टे उपकरण को आगे के पैर में निलंबन तंत्र, स्टे उपकरण और चेक उपकरण में विभाजित किया गया है- निलंबन उपकरण: इंटरोससियस मेडियस/सस्पेंसरी लिगामेंट लगभग, यह कार्पल हड्डियों और मेटाकार्पस की बाहर की पंक्ति से जुड़ जाता है। यह मेटाकार्पल हड्डी की हथेली की सतह पर दूर से चलता है और फिर समीपस्थ को मेटाकार्पोफैंगल जोड़ से विभाजित होता है, जिसमें प्रत्येक सीसमॉइड से जुड़ी एक छोटी शाखा होती है।

स्टे उपकरण: सेराटस वेंट्रैलिस मांसपेशिशरीर के आगे के भाग का समर्थन करता है, और स्कैपुला के कॉस्टल पक्ष को ग्रीवा कशेरुक और कपाल पसलियों पर लगाव के बिंदुओं से जोड़ता है। इसमें एक कोमल परत होती है जो मांसपेशियों के आराम करने पर शरीर को निलंबित कर देती है। बाइसेप्स ब्राचईमांसपेशि इस भूमिका को निभाते हैं। इसका कोलेजनस टेंडन मांसपेशियों की लंबाई बढ़ाता है और कोहनी के पास विभाजित होता है। रेडियल ट्यूबरोसिटी पर शॉर्ट टेंडन चिपकता है, लॉन्ग टेंडन दूर से जारी रहता है और एक्सटेंसर कर्पाई रेडियलिस मांसपेशी के साथ मिश्रित होता है, ये मेटाकार्पस के समीपस्थ छोर पर जुड़ता है। इस प्रकार, बाइसेप्स में कंधे, कोहनी और कार्पल जोड़ों के पतन के बिना आराम करने में सक्षम होने का प्रावधान है।

चेक उपकरण: सुपेरफिसिअल डिजिटल फ्लेक्सर मांसपेशी, कार्पस के पीछे एक मोटी कण्डरा के रूप में जारी रहती है। एक्सेसरी या सुपीरियर चेक लिगामेंट इसका टेंडिनस रेडियल हेड होता है जो इस बिंदु पर पेशी से जुड़ता है। टेंडन दूर से जारी रहते हैं और मेटाकार्पो फैंलिंजिअल जोड़ सेस्लिप्स में विभाजित होते हैं, जो पेस्टर्न जोड़ के औसत दर्जे और पार्श्व पहलू से जुड़ते हैं। इसलिए डिस्टल रेडियस से पेस्टर्न तक एक लिगामेंट का कनेक्शन होता है जो मांसपेशियों के संकुचन के बिना कार्पल और मेटाकार्पोफैलिंजिअल जोड़ के विस्तार को रोकने में मदद करता है। डीप डिजिटल फ्लेक्सर भी कार्पस के समीप एक मोटी कण्डरा बनाता है। एक्सेसरी लिगामेंट या चेक लिगामेंट, मेटाकार्पस के बीच में टेंडन से जुड़ता है। फिर वे सुपरफिसिअल डिजिटल फ्लेक्सर कण्डरा के द्विभाजन के माध्यम से जारी रहते हैं, मेटाकार्पोफैंगल के जोड़ पर इंटरसेमोइडियन नाली के माध्यम से, पेस्टर्न के ऊपर और डिस्टल फलिंक्स पर जारी रहते हैं। मेटाकार्पल और डिस्टल फलिंक्स के बीच यह लिगामेंट का ऊतक मेटाकार्पोफैलिंजिअल, पेस्टर्न और कोफिन जोड़ों के विस्तार को रोकने में मदद करता है।

पिछले पैर में स्टे उपकरण को पेटेलर लॉकिंग, पारस्परिक तंत्र और चेक उपकरण में विभाजित किया गया है

पटेलर लॉकिंग उपकरण: यह अश्वों के घुटनों/ स्टिफ़ल की विशिष्ट संरचना है जो लॉकिंग को सक्षम बनाता है इसमें औरकई संरचनाएं शामिल हैं। पेटेला के ग्लाइडिंग मूवमेंट के लिए ट्रोक्लियर ग्रूव चौड़ा होता है और मेडियल ट्रोक्लियर रिज बड़ा, चौड़ा और गोल होता है। घोड़े के तीन पेटेलर स्नायुबंधन; लेटरल,मीडियल और मध्य (मिडिल) पटेलर स्नायुबंधन पटेला को टिबिया से बांधते हैं। स्टिफ़ल के सामान्य मुड़ने और सीधा होने के दौरान पटेला ट्रोक्लियर ग्रूव में सरकता है , जब घोड़ा अपना भार पिछले पैर पर टिकाता है तो स्टिफ़ल एक निश्चित बिंदु से आगे बढ़ सकता है। यह पटेला को ट्रोक्लियर ग्रूव के समीपस्थ छोर तक ले जाने का कारण बनता है, एक औसत दर्जे का मोड़, जिसके परिणामस्वरूप मध्य और मीडियल पेटेलर स्नायुबंधन के बीच मीडियल रिज होता है, जिसमें पेटेलर कार्टिलेज ट्रोक्लियर ट्यूबरकल पर हुक होता है। इस प्रकार पटेला बंद होता है और इसका आगे झुकना संभव नहीं रहता। इसके परिणामस्वरूप एक स्थिर संयुक्त जोड़ बन जाता है और पैर को इस स्थिति में बनाए रखने के लिए मांसपेशियों की गतिविधि की आवश्यकता नहीं होती है; इस प्रकार इस पैर पर अश्वा भार को स्थिर रख आराम कर सकता है। पटेला को मुक्त करने के लिए, घोड़ा अपने वजन को दूसरे अंग में स्थानांतरित करता है और क्वाड्रिसेप्स पटेला को खींचता है। फिरस्टिफल मुड़ जाता है और पटेला ट्रोक्लियर ग्रूव में वापस आ जाता है।

पारस्परिकतंत्र (रेसिप्रोकल सिस्टम): पारस्परिक तंत्र टिबिया के दोनों ओर मांसपेशियों से बना एक तंत्र है। अग्र भाग पर पेरोनियस टर्टियस मसल है, जो ट्रोक्लीया और लेटरल कॉनडाइल के बीच निकलकर, टारसो-मेटोटार्सल क्षेत्र मेंद्विभाजित होता है। यह रेशेदार पेशी यह सुनिश्चित करती है कि स्टिफ़ल और होक जोड़ का फ्लेक्सन एक साथ हो। पिछले सतह पर सतही डिजिटल फ्लेक्सर और गस्त्रोक्नेमिअस मसल बण्डल रहते हैं। गस्त्रोक्नेमिअस का बैंड फीमर के लेटरल सुप्राकॉन्डिलॉइड ट्यूबरोसिटी से निकलकर कैल्केनस पर जुड़ता है। ये दो मांसपेशियां सुनिश्चित करती हैं कि जब स्टिफ़ल विस्तार में हो तो हॉक भी विस्तार में हो। इस प्रकार इन संरचनाओं को उनका नाम पारस्परिक क्रिया से प्राप्त होता है जब फीमर आगे की तरफ चलती है तो पैर का निचला भाग पिछले की तरफ झूलता है और एसा ही इसके विपरीत भी होता है। यह उपकरण यह भी सुनिश्चित करता है कि जब पटेला बंद (लोक) हो जाता है तो हॉक भी स्थिर हो जाता है। ये परिणाम बिना मांसपेशियों की थकान के प्राप्त होते हैं।

सीबीडी कॉपः 2030 तक 30 प्रतिशत धरती की रक्षा करने का लक्ष्य

जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (सीबीडी) के पक्षकारों के 15वें सम्मेलन (कॉप 15) समाप्त हो गया। इस सम्मेलन में 2030 तक कम से कम 30 प्रतिशत धरती की रक्षा करने का लक्ष्य तय किया गया। की बात कही गई है। कुल मिलाकर 23 लक्ष्य तय किए गए, जिन्हें दुनिया को 2030 तक हासिल करना है। सम्मेलन में यह भी प्रस्ताव पारित किया गया कि अमीर देश, विकासशील देशों को हर साल 30 बिलियन डॉलर की सहायता देंगे, ताकि उनके पारिस्थितिक तंत्र को बचाया जा सके। यह प्रस्ताव शिखर सम्मेलन में प्रतिनिधित्व कर रहे देश चीन ने प्रस्तुत किया।

वैज्ञानिकों का कहना है कि एक लाख प्रजातियां खतरे में हैं, इन सब को बचाने के लिए अगले दशक की कार्रवाई तय करना, 2025 तक विकासशील देशों की वित्तीय सहायता बढ़ाकर 20 बिलियन डॉलर सालाना करने का प्रस्ताव है। 2030 तक इसे बढ़ाकर हर साल 30 बिलियन डॉलर करने का प्रस्ताव है।

इसमें देशों को यह सुनिश्चित करने और सक्षम बनाने के लिए भी कहा गया है कि 2030 तक स्थलीय, आंतरिक और तटीय और समुद्री क्षेत्रों का कम से कम 30 प्रतिशत प्रभावी ढंग से संरक्षित और प्रबंधित करना शामिल है। मसौदे में स्वदेशी लोगों के अधिकारों की रक्षा करने वाली भाषा शामिल है, जो प्रचारकों की एक प्रमुख मांग रही है।

समझौते के बिंदुओं का बड़े पैमाने पर संरक्षणवादियों द्वारा स्वागत किया गया था, लेकिन अभी भी 196 हस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा जैव विविधता पर सम्मेलन को अंतिम रूप देने से पहले इस पर सहमति की जरूरत है।

मॉन्ट्रियल में वार्ता की शुरुआत करते हुए, संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस ने चेतावनी देते हुए कहा कि मानवता सामूहिक विलुप्ति का हथियार बन गई है। उन्होंने पार्टियों से प्रकृति के साथ शांति समझौता करने का आह्वान किया। प्रकृति के लिए अभियान के ब्रायन ओ%डोनेल ने कहा, दुनिया की कम से कम 30 प्रतिशत भूमि और महासागरों की रक्षा और संरक्षण के लक्ष्य को शामिल करके, मसौदा के बिंदुओं, समुद्र और भूमि संरक्षण के इतिहास में इसे सबसे बड़ा संकल्प बनाता है। लेकिन मसौदे के कुछ बन्दुओं में कमी देखी गई है। ब्रिटेन की रॉयल सोसाइटी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ बर्ड्स की जॉर्जीना चांडलर ने कहा कि वह 2050 तक पारिस्थितिक तंत्र को बहाल करने के लिए प्रस्तावित किए गए उपायों की कमी के बारे में चिंतित है। उन्होंने कहा हम मूल रूप से 28 साल के समय तक प्रगति को माप नहीं रहे हैं, जो कि एक पागलपन है। विवाद का एक अन्य प्रमुख मुद्दा वित्तपोषण तंत्र है। विकासशील देश, ब्राजील के नेतृत्व में, ग्लोबल नॉर्थ की संकल्प के लिए एक नए कोष के निर्माण की मांग कर रहे हैं। लेकिन मसौदा इसके बजाय एक समझौते का सुझाव देता है जो मौजूदा वैश्विक पर्यावरण सुविधा के भीतर एक ट्रस्ट फंड के रूप में होगा।

पर्यवेक्षकों ने कॉप 15 सम्मेलन के खतरे में पड़ने की चेतावनी दी थी क्योंकि विकासशील देशों ने एक बिंदु पर वार्ता से बाहर निकलने के साथ-साथ अमीर दुनिया को प्रयासों के लिए कितना भुगतान करना चाहिए, इस पर विवाद था।

लेकिन चीनी पर्यावरण मंत्री हुआंग रुनकिउ ने कहा कि वह आम सहमति के लिए बेहद आश्वस्त थे और उनके कनाडाई समकक्ष स्टीवन गुइलबौल्ट ने इसमें जबरदस्त प्रगति होने की बात कही। 23 लक्ष्यों में पर्यावरणीय रूप से विनाशकारी कृषि सब्सिडी को कम करना, व्यवसायों को उनके जैव विविधता प्रभावों का आकलन और रिपोर्ट करने के लिए कहना और आक्रामक प्रजातियों के संकट से निपटना शामिल है।

लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि अमीर देश विकासशील देशों को कितनी धन राशि देंगे, जहां धरती की अधिकांश जैव विविधता है। निम्न आय वाले देशों का कहना है कि विकसित देश अपने प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करके समृद्ध हुए हैं और इसलिए उन्हें अपने स्वयं के संसाधनों की रक्षा के लिए अच्छा भुगतान किया जाना चाहिए।

विकासशील देशों के लिए वर्तमान वित्तपोषण लगभग 10 बिलियन डॉलर प्रति वर्ष होने का अनुमान है। कई देशों ने हाल ही में नए संकल्प लिए हैं। यूरोपीय संघ ने 2027 तक की अवधि के लिए सात बिलियन यूरो का संकल्प लिया है, जो इसके पहले किए गए वादे से दोगुना है।

मिश्रित खेती, लाभ का धंधा

शुरू से ही भारत में मिश्रित खेती का प्रचलन था। हर किसान के पास एक बैल जोड़ी, अनाज को स्थानान्तरण के लिये बैलगाड़ी, आवश्यकता के लिये एक या दो गाय, भैंस का होना सामान्य बात हुआ करती थी। परंतु जैसे-जैसे जनसंख्या का बोझ बढ़ा, हमारी आवश्यकता बढ़ी और बढ़ती मांग की पूर्ति के लिये कृषि से अधिक उत्पादन की जरूरत पडऩे लगी। हमने कृषि के लिये उन्नत बीज तैयार किये, उक्त बीज के पेट भरने के लिये रसायनिक उर्वरक तथा सिंचाई जल की आवश्यकता बढ़ती गई और परिणामस्वरूप छोटे, मध्यम तथा बड़े बांधों का निर्माण शुरू हुआ ताकि कृषि की प्रमुख आवश्यकता जल की भरपाई की जा सके। कृषि की उत्पादकता बढ़ाने के प्रमुख तीन श्रोत अच्छा बीज, भरपूर उर्वरक तथा जल को पाकर उत्पादन की क्षमता दो-तीन गुना बढ ग़ई एक और जहां हम अनाज बाहर से बुलाते थे अब बाहर भेजने के लिये भी हमारी क्षमता बढ़ गई। बढ़ती जनसंख्या, पारिवारिक बंटवारे से घटती खेती की जोत और कृषि के लिये प्रमुख आदानों की बढ़ती कीमतों से हमारी कृषि नफा के बजाय नुकसान देने लगी। कृषि में नवीनीकरण की दौड़ में हमारी प्रगति तो हुई इसमें कोई शंका नहीं परंतु लाभकारी खेती में हम पिछड़ गये तब जाकर हमें हमारी कृषि की पुरानी पद्धति याद आई जिसमें हम पशुपालन, करके खेती से मिले अवशेषों का भरपूर उपयोग करके अतिरिक्त आय भी करते थे। मशीनीकरण नि :संदेह हमारी जरूरत है परंतु पशुपालन को त्यागना हमारी मजबूरी कतई नहीं थी। बड़े बुजुर्ग कहते थे हमारे देश में दूध की नदियां बहती थीं वह कल्पना सिमट कर दूध के पैकेट में रह गई, खैर देर आये दुरूस्त आये आज की स्थिति में अकेली खेती से हमारी आवश्यकताएं पूरी होना असंभव है खेती के साथ पशुपालन, पशु होंगे तो गोबर होगा, मूत्र होगा, गोबर के उपयोग से अच्छी गुणवत्ता का जैविक खाद, गोबर गैस को बनाने के लिये गोबर ताकि धुआं रहित रसोई हो सके और हमारा जीवन स्तर ऊंचा उठ सके। खेती के अवशेषों का पर्याप्त उपयोग करने के लिये बकरी पालन भी किया जा सकता है जिस पर अल्प खर्च में बड़ा पैसा हाथ लग सकता है। वर्तमान में कृषि से जुड़ा मधुमक्खी पालन एक ऐसी जरूरत है जिसमें हमारी कृषिका उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। मधुमक्खी पालन से आम के आम गुठलियों के दाम वाली बात चरितार्थ होती है। मधुमक्खी पालन करने से शहद के अलावा हमारी कृषि के उत्पादन में सकारात्मक परिणाम प्राप्त होते हैं। सूर्यमुखी फसल में तो यदि मधुमक्खी की क्रियाशीलता ना हो तो बड़े-बड़े फूल दाने विहीन पोचे रह जायेंगे। सर्वेक्षण से ज्ञात हुआ है कि कम से कम 100 फसलों के फूलों से परागकण का स्थानान्तरण इस कीट के द्वारा करके उन्हें दाने बनने की क्रिया में मदद मिलती है। उल्लेखनीय है कि खेती के कई कार्यों के लिये सरकार द्वारा प्रशिक्षण की व्यवस्था भी की जाती है। जैसे मशरूम उत्पादन और मधुमक्खी पालन आदि। खेत में यदि कुछ भूमि में फल वृक्ष लगा लिये जायें तो पैसा ही मिलेगा। नींबू के पौधों को थोड़ी सी देखभाल के बाद फलों के क्रय से अच्छी आमदनी मिल सकती है। इस प्रकार यदि हम मिश्रित खेती करना शुरू कर दें तो हमारी कई समस्याएं अपने आप समाप्त हो जाएंगे और धनार्जन भी होगा, साथ में वातावरण भी शुद्ध रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है।

रंग लाई मेहनत, छह महीने में कमाए सात लाख, 40 से 50 महिलाओं को सालभर रोजगार देने का दावा

हरदा की बेटी ने फूलों से बनाया देश का पहला एनर्जी ड्रिंक

» जिले के सिरकंबा गांव में किया जा रहा तैयार

» इंदौर ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में लेंगी हिस्सा

» जियो मार्ट, बिग बास्केट व अन्य प्लेटफॉर्म पर प्रोडक्ट लाएंगे

» उत्तराखंड और महाराष्ट्र राज्य में भी डिस्ट्रीब्यूटर्स बनाए

» भोपाल, इंदौर में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के माध्यम से पाउडर बेच रहे

हरदा | जागत गांव हमार

जिले के सिरकंबा गांव की बेटी ने खेती में सफलता के झंडे गाड़ दिए हैं। न केवल खेती में नवाचार किया, बल्कि खेती को व्यावसायिक रूप देकर इसे लोगों की सेहत से भी जोड़ दिया है। अर्चना नागर धाकड़ (38 साल) ने बताया कि वह अपनी मां निर्मला बाई की मदद से पिछले पांच साल से फूलों की खेती कर रही हैं। मां-बेटी दोनों मिलकर फूलों की खेती को एक नया मुकाम देने में जुटी हैं। इन्हीं फूलों के रस से उन्होंने इम्युनिटी बूस्टर ड्रिंक बनाया है। इसकी खेती करने में शुरुआती दो साल सफलता नहीं मिली। तीसरे साल बीज से अच्छे पौधे बने और फूल आए। इसके बाद सही खेती करने का आइडिया समझ आया। इसके बाद कोरोना आया, जिसमें पता चला कि हेल्थ इम्युनिटी कितनी जरूरी है। इस ड्रिंक को सेज नाम दिया है।

उन्होंने बताया कि रोजेला यह औषधीय पौधा है। इससे बना ड्रिंक इम्यूनिटी बूस्टर है। इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में विटामिन सी है। इस पौधे का वैज्ञानिक नाम हिबिस्कस सबदरिफा है। यह साउथ अफ्रीका का फूल है। इसे सामान्य भाषा में रोजेला कहा जाता है। इस फूल को एक आस्ट्रेलियन बेस्ड कंपनी के प्रतिनिधियों की मदद से हरदा बुलवाया गया था। इसी साल मई के माह से इम्युनिटी बूस्टर ड्रिंक का उत्पादन शुरू किया है। छह माह हुए हैं प्रोडक्ट को लांच किए हुए। सिरकंबा गांव सहित कुछ अन्य जगह में पंद्रह से बीस एकड़ में फूलों की खेती की जा रही है। हरदा जिले के उन्नत किसान मधुसूदन धाकड़ की पुत्री हैं अर्चना नागर धाकड़।

सरकार की मंशा के अनुरूप कर रहीं काम

अर्चना ने बताया कि सरकार की भी मंशा यही है कि किसान परंपरागत खेती से आगे बढ़कर व्यावसायिक खेती करे, ताकि किसान की आय को दोगुनी की जा सके। अर्चना ने बताया कि इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने जाब न करते हुए खेती किसानी में किस्मत आजमाई है।

यह आई चुनौती

पहली बार बीज नकली मिल गए, जिससे परेशानी हुई। बीज उन्होंने आस्ट्रेलिया से बुलवाए थे। वहां की कंपनी ने बीज भेजे। कंपनी औ किसान के बीच भाषायी परेशानी हुई। इसके बाद कंपनी और किसान के बीच ट्रांसलेटर ने संपर्क साधा। ट्रांसलेटर ने अर्चना के पिता को फूल और खेती की जानकारी दी, लेकिन पिता को पूरी बात सही तरीके से समझ नहीं आई। क्योंकि पिता को अंग्रेजी कम आती थी। इसके अलावा फूल को हरदा के वातावरण के हिसाब से एडजस्ट होने में थोड़ा समय लगा।

फरवरी में आएंगे दो और फ्लेवर

उन्होंने बताया कि अभी बाजार में इम्यूनिटी बूस्टर ड्रिंक नेचुरल मसाला फ्लेवर में उपलब्ध है। इसको मिश्री और हिमालया पिंक साल्ट फ्लेवर में भी तैयार किया गया है, जिसे बाजार में फरवरी में लांच किया जाएगा।

ग्लोबल समिट में अपना प्रोडक्ट रखेंगी

इंदौर में होने जा रहे ग्लोबल समिट में अर्चना अपने इम्युनिटी बूस्टर ड्रिंक की जानकारी देंगी। ड्रिंक के बारे में अर्चना ने कहा कि यह पूरी तरह प्राकृतिक रूप से बना है। इसमें किसी तरह का कलर, न ही केमिकल का उपयोग किया गया है। प्राकृतिक रूप से बने होने के बाद इसमें शरीर की इम्युनिटी पावर बढ़ाने की क्षमता अधिक है। इसका सेवन करके हम कोरोना के खतरों से बच सकते हैं। रोजेला के फूल में विटामिन सी अधिक मात्रा है।

सिरकंबा में होता है तैयार

अर्चना ने बताया कि फूलों को तोड़कर सूखाया जाता है। इसके बाद इसका पाउडर बनाकर इसे इम्युनिटी बूस्टर ड्रिंक में तब्दील किया जाता है। इसे लोगों तक पहुंचाने के लिए तीन प्लेटफार्म तैयार किए हैं, जिनमें ऑनलाइन, आफलाइन और सुपर मार्केट के माध्यम से इसे लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि अभी तक करीब बीस लाख रुपए खर्च किए हैं। इसमें दस लाख की राशि ड्रिंक तैयार कराने में खर्च हुई है। ड्रिंक को बेचने पर अब तक करीब सात लाख रुपए की आय प्राप्त हुई है।

लोगों को समझाना चुनौती

अर्चना बताती है कि कोरोना के कारण लोग शारीरिक रूप से कमजोर हुए हैं। इसलिए हमें हमारी शरीर की इम्युनिटी पावर को बढ़ाने की जरूरत है। ऐसे में फूलों से बना यह इम्युनिटी बूस्टर ड्रिंक न केवल हमारी इम्युनिटी पावर बढ़ाएगा।वहीं हमें कोरोना के खतरों से भी दूर रखने में मदद करेगा। ड्रिंक बनाने के बाद शुरुआत में लोगों को समझाने में काफी समय लगा, लेकिन जब लोगों को इसके फायदे समझ आने लगे तो इसे पसंद किया जाने लगा। इसे लोगों को आसानी से समझाने के लिए इसे एनर्जी ड्रिंक बताया गया।

-किसानों ने जाना बीजामृत के निर्माण और उपयोग

किसानों की आय बढ़ाने प्राकृतिक खेती वर्तमान की आवश्यकता

टीकमगढ़ | जागत गांव हमार

कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा निवाड़ी विकासखंड के 45 किसानों को प्राकृतिक खेती पर डॉ. बीएस किरार प्रधान वैज्ञानिक एवं प्रमुख डॉ. आरके प्रजापति वैज्ञानिक डॉ. एसके जाटव डॉ. आईडी सिंह जयपाल छिगारहा और उद्यान विभाग से राजू अहिरवार उद्यान विकास अधिकारी ने व्याख्यान दिया। प्रशिक्षण में वैज्ञानिकों ने प्रकृति खेती को वर्तमान की आवश्यकता बताया गया, क्योंकि वर्तमान में सब्जियों, फलों और खाद्यान्न फसलों के उत्पादन के असंतुलित व अंधाधुंध मात्रा में रसायनिक, दवाएं और शाकनाशी दवाओं का प्रयोग किया जा रहा है। जिसमें मनुष्यों में बहुत सी छोटी और बड़ी बीमारियां अत्याधिक मात्रा संख्या में पनप रही हैं। साथ ही भूमि, जल एवं वायु दूषित होते जा रहे हैं। इन सब का समाधान प्राकृतिक खेती और जैविक खेती है। प्रशिक्षण में वैज्ञानिकों ने बीजामृत, जीवामृत, घनजीवामृत और संजीवक के निर्माण और उपयोग का तरीका बताया गया।

खड़ी फसल में छिड़काव करना

बीजामृत के घोल से बीजोपचार किया जाता है। घनजीवामृत में गाय के गोबर, मूत्र, गुड, बेसन एवं पीपल/बरगद के पेड़ के नीचे की 250 ग्राम मिट्टी का मिश्रण बनाकर खेत में डालना और जीवामृत गाय का गोबर, मूत्र, बेसन एवं पेड़ के नीचे की मिट्टी को पानी में घोलकर एक सप्ताह बाद खड़ी फसल में छिड़काव करना या सिंचाई के साथ देना चाहिए। प्राकृतिक खेती में खेतों की कम जोतइयां की जाती है। दो कतारों के बीच में घास-फूस और पत्तियों से आच्छादन (मुल्चिंग) करना चाहिए।

अंतर्वर्तीय फसलें बोना चाहिए

मुख्य फसल के साथ सहायक फसल अंतर्वर्तीय फसलें बोना चाहिए। कीट प्रबंधन के लिए नीमास्त्र, ब्रम्हास्त्र और आग्नेयास्त्र आदि घोल बनाकर फसलों रस चूसक और काटने वाले कीटों के प्रबंधन के लिए समय-समय पर छिड़काव करते रहना चाहिए। प्रत्येक किसान को कुल रकबा के 10-20 फीसदी तक भूमि का प्राकृतिक खेती से सब्जियों और अनाज का उत्पादन कर अपने परिवार को उत्तम स्वास्थ्य बनाएं। शरीर से बीमारियां दूर भगाएं। प्रशिक्षण में रबी सब्जियों में लगने वाले कीट ब्याधियों के प्रबंधन की जानकारी दी गई।

आजीविका सुरक्षा विषय पर पांच दिन दिया प्रशिक्षण

कृषि वैज्ञानिकों ने बताया कैसे स्वरोजगार का साधन मशरूम उत्पादन

उज्जैन। जागत गांव हमार

कृषि विज्ञान केन्द्र उज्जैन द्वारा कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत मशरूम उत्पादन तकनीकी द्वारा आजीविका सुरक्षा विषय पर पांच दिवसीय प्रषिक्षण कार्यक्रम का आयोजन पांच दिन तक डॉ. आरपी शर्मा, प्रधान वैज्ञानिक एवं प्रमुख के मार्गदर्शन में सफल आयोजन किया गया। डॉ. शर्मा ने कार्यक्रम आयोजन का लक्ष्य और युवाओं के लिए यह किस तरह स्वरोजगार का साधन हो सकता है के बारे में विस्तार से चर्चा की। डॉ. एचआर जाटव, वैज्ञानिक कृषि विस्तार द्वारा मशरूम के प्रकार, मशरूम उत्पादन तकनीकी प्रयोगिक कार्य जैसे मशरूम उत्पादन के लिए माध्यमम तैयार करना, माध्यम में बीजाई करना आदि के बारे में विस्तृत जानकारी दी गयी। जिससे प्रसार शिक्षा के महत्वपूर्ण सिद्धांत करके सीखो देखकर विश्वास करो के आधार पर प्रतिभागी प्रशिक्षण में कौशल प्राप्त कर एक सफल उद्यमी बन सकें।

कीट से इस तरह करें बचाव

डॉ. डीके, सूर्यवंशी वैज्ञानिक पौध संरक्षण द्वारा मशरूम में लगने वाले विभिन्न कीट एवं रोगों का जैविक तरीके से कैसे प्रबंधन किया जाए के बारे में विस्तृत जानकारी दी गयी। डॉ. डीएस तोमर, वरिष्ठ वैज्ञानिक शस्य विज्ञान द्वारा मशरूम उत्पादन का अर्थशास्त्र एवं मशरूम उत्पादन में लगने वाली लागत के बारे में विस्तृत जानकारी दी गयी। डॉ. एसके कौशिक, वरिष्ठ वैज्ञानिक पौध प्रजनन द्वारा मशरूम उत्पादन में सहयोगी संस्थान एवं मशरूम स्पान के स्त्रोत के बारे में विस्तार से जानकारी दी गयी।

मशरूम का कैसे मूल्य को बढ़ाया जाए

डॉ. रेखा तिवारी, वरिष्ठ वैज्ञानिक गृह विज्ञान द्वारा मशरूम में मूल्य संवर्धन कर कैसे मूल्य को बढ़ाया जाए के बारे में विस्तृत जानकारी दी गयी। डॉ. मोनी सिंह, वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी, गृह विज्ञान द्वारा मशरूम एवं मशरूम उत्पाद जैसे मशरूम अचार, मशरूम पापड़, मशरूम नगेटस, मशरूम चिप्स आदि उत्पादों को बनाने की विधियों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गयी। साथ ही मशरूम में पाए जाने वाले विभिन्न पोषक तत्वों के बारे में भी बताया गया।

मशरूम उत्पादन पर फिल्म दिखाई

गजाला खान, वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी, कम्प्यूटर साइंस द्वारा मशरूम उत्पादन पर वीडियो फिल्म दिखाई गई। साथ ही मशरूम के ऑनलाईन मार्केटिंग के बारे में जानकारी दी गयी। राजेन्द्र गवली, तकनीकी अधिकारी मृदा विज्ञान के द्वारा मशरूम की गुणवत्ता एवं विशेषता के बारे में विस्तृत जानकारी दी गयी।

-किसानों को मिलेगा लाभ, आएगी कृषि क्षेत्र में आएगी क्रांति

अब कृषि क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए लेंगे अंतरिक्ष विभाग की मदद

भोपाल। जागत गांव हमार

किसानों को आमदनी बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा लगातार नई तकनीकों को बढ़ावा दिया जा रहा है। ताकि कृषि क्षेत्र में जोखिम को कम करके फसल उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाई जा सके। इसलिए अब भारत सरकार ने कृषि क्षेत्र को अंतरिक्ष से जोड़ने का फैसला किया है। हाल ही में कृषि और किसान कल्याण विभाग और अंतरिक्ष विभाग ने कृषि-निर्णय समर्थन प्रणाली विकसित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं, जिससे मौसम का पूर्वानुमान, फसल उत्पादन का आकलन, मिट्टी का डाटा, फसल में नुकसान का सर्वे और प्राकृतिक आपदाओं का भी आकलन करने में मदद मिलेगी। खेती को आसान बनाने के लिए समय-समय पर किसानों के लिए भी गाइडलाइंस जारी की जाएंगी, जिससे किसानों को भी फसल के उत्पादन के साथ-साथ उत्पादकता बढ़ाने में मदद मिलेगी। जोखिम से पहले से ही किसान सतर्क हो जाएंगे और फसल को सुरक्षित रखना भी आसान हो जाएगा।

किसानों को होंगे यह लाभ

इस अवसर पर अपने संबोधन में केन्द्रीय मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा कि कृषि के क्षेत्र में एक नया आयाम जुड़ रहा है। अंतरिक्ष विज्ञान के माध्यम से कृषि क्षेत्र में क्रांति की शुरुआत हो रही है। कृषि विभाग और अंतरिक्ष विभाग के बीच हुए समझौते से कृषि क्षेत्र की ताकत और बढ़ेगी। अगर यह ज्ञान किसानों तक पहुंचेगा तो उनके उत्पादन के साथ-साथ उत्पादकता बढ़ेगी। उत्पादन की गुणवत्ता भी बढ़ेगी और निर्यात के अवसर भी बढ़ेंगे।

क्रांतिकारी बदलाव आएगा

कृषि मंत्री ने बताया कि एग्रीस्टैक पर भी कृषि विभाग काम कर रहा है। किसान की आय बढ़ाने और पूर्वानुमान लगाकर उसे नुकसान से बचाने के लिए काम किया जा रहा है। फसल का आकलन, राज्यों को आवंटन, क्षेत्र को सूखा घोषित करने के लिए सर्वेक्षण, आपदा आकलन- तकनीक अपनाने से ये सभी कार्य आसान हो जाएंगे। यह तकनीक कृषि क्षेत्र के साथ-साथ देश के लिए भी बहुत फायदेमंद है। एग्रीस्टैक के पूरा होने के बाद कृषि के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव आएगा।

कैसे काम करता है री-सैट-1

अंतरिक्ष विभाग के सचिव एस सोमनाथ ने कहा कि री-सैट-1ए भारत का पहला रडार इमेजिंग सैटेलाइट है, जिसे 14 फरवरी, 2022 को लॉन्च किया गया था। री-सैट-1ए एक बारहमासी उपग्रह है। वनस्पति में गहराई तक प्रवेश कर सकता है। यह प्रकाश की स्थिति से भिन्न उच्च रेजोल्यूशन वाली भू-स्थानिक छवियां ले सकता है। यह समझौता ज्ञापन भारतीय कृषि के समावेशी, आत्मनिर्भर और सतत विकास के लिए डिजिटल आधार प्रदान करेगा।

देशभर में फैला रहे प्राकृतिक उत्पाद

किसान के लिए वरदान बनी सोशल नेटवर्किंग

खरगोन। जागत गांव हमार

सोशल मिडिया के आने के बाद से कई किसानों ने इसको एक अवसर के समान उपयोग कर अपने व्यवसाय को बढ़ाया है। महेश्वर में बड़वी के किसान भगवान राव पिछले सात साल से अपने 4 एकड़ खेत पर प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। इस खेती को अपना कर वे अपने आप मे बहुत संतुष्ट भी हैं और खुश भी हैं। इसका एक कारण ये भी है उनसे गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान सहित मप्र के कई शहरों के उपभोक्ता सोशल नेटवर्किंग से जुड़े हैं। इससे उनकी फसल आते ही बिक जाती है। 6 बीघा खेत मे उन्होंने ऐसा प्रबंधन किया जिससे वे कई तरह के अनाज और दालों के अलावा सब्जी और फल वाली फसलें भी कर लेते हैं। इनके प्रबंधन का उत्कृष्ठ उदाहरण यह भी है कि वे हर समय उनके खेत में हरियाली रहती है। कुछ वर्षों से वे गन्ने की खेती को भी प्राथमिकता दे रहें है। इसके पीछे एक कारण यह भी है कि वे स्वयं गुड़ भी बनाते हैं।

फ्लेवर बनाने में हुए सफल

किसान भगवान राव ने अपनी रचनात्मक्ता का सफल प्रयोग गुड़ की बर्फी के साथ किया है। वे इलाइची, सोंठ और तीन के फ्लेवर में 20 से 30 ग्राम में बर्फी बना रहे हैं। गन्ने से वे 18 से 20 क्विंटल गुड़ बना रहे हैं। जिसकी मांग जयपुर, अहमदाबाद सहित महाराष्ट्र के कई स्थानों पर अपने मुनाफे के साथ भेज रहे हैं।

दुधारू पशु, घोड़ा, गधा, खच्चर, ऊंट,टट्टू, सांड, भैंस पाड़ा एवं अन्य पशु भेड़, बकरी, सूकर, खरगोश आदि शामिल

इंदौर में पशुधन बीमा योजना के क्रियान्वयन के दिशा निर्देश जारी

इंदौर। जागत गांव हमार

मध्यप्रदेश राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम के अंतर्गत राष्ट्रीय पशुधन मिशन में रिक्स मैनेजमेंट एंड लाइवस्टॉक इश्योरेंस (पशुधन बीमा) योजना के वर्ष 2022-23 में जिले में क्रियान्वयन के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। उप संचालक पशुधन एवं डेयरी ने बताया कि पशुधन बीमा योजना के जिले में क्रियान्वयन के निर्देश जारी किए हैं, जिसमें इस योजना में सभी पशुधन, देशी एवं संकर दुधारू पशु, भारवाही पशु जैसे घोड़ा, गधा, खच्चर, ऊंट,टट्टू, सांड, भैंस पाड़ा एवं अन्य पशु भेड़, बकरी, सूकर, खरगोश आदि शामिल किए गए हैं। योजना के अंतर्गत प्रति परिवार एक हितग्राही के पांच पशुओं का बीमा प्रीमियम अनुदान पर बीमा किया जा सकता है, लेकिन इसमें भेड़, बकरी, सूकर, खरगोश के लिए दस पशुओं की संख्या को एक केटल इकाई माना गया है। भेड़, बकरी, सूकर, खरगोश का बीमा प्रीमियम अनुदान पर प्रति परिवार एक हितग्राही के अधिकतम 5 केटल यूनिट तक बीमा किया जाना है। परिवार की परिभाषा मनरेगा गारंटी अधिनियम 2005 के अनुसार रहेगी।

तीन वर्ष तक का होगा बीमा

उप संचालक ने बताया कि पशुओं का बीमा एक वर्ष, दो वर्ष एवं तीन वर्ष के लिए किया जाएगा। एक वर्ष के लिए बीमा प्रीमियम की दर 3.5 प्रतिशत, 2 वर्ष की अवधि के लिए 6.5 प्रतिशत और 3 वर्ष की अवधि के लिए 9 प्रतिशत दर निर्धारित की गई है। बीमा प्रीमियम पर हितग्राही से सेवा शुल्क नहीं लिया जाएगा। बीमा प्रीमियम पर अनुदान एवं हितग्राही को अंशदान दिया जाएगा। उप संचालक ने जिले के सभी पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ/पशु चिकित्सक विस्तार अधिकारी को पशुधन बीमा योजना के क्रियान्वयन और दिशा निर्देश और लक्ष्य पूर्ति के लिए आवश्यक कार्रवाई के निर्देश जारी किए हैं।

कृषि विज्ञान केन्द्र पर किसान दिवस का आयोजन

प्राकृतिक खेती के प्रति किसानों को जागरुक करने की जरूरत

लहार। जागत गांव हमार

कृषि विज्ञान केंद्र पर राष्ट्रीय किसान दिवस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर भिंड जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आए किसानों को प्राकृतिक खेती के बारे में जागरूकता लाने के लिए वैज्ञानिकों द्वारा प्राकृतिक खेती के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला गया। किसान दिवस के अवसर पर किसानों को संबोधित करते हुए केंद्र के प्रधान वैज्ञानिक एवं प्रमुख डॉ. एस. पी. सिंह द्वारा किसान दिवस की महत्ता के बारे में अवगत कराया कि हर वर्ष पूरे देश में 23 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री एवं किसान नेता चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस के अवसर पर किसान दिवस का आयोजन किया जाता है। चौधरी चरण सिंह हमेशा किसानों की फसलों पर आने वाली लागत कम करने तथा किसानों के उत्पादों का वाजिब मूल्य दिलाने के लिए संघर्ष करते रहे हैं। इसी क्रम में आज समय की मांग है कि किसानों की फसलों की लागत कम हो और खेती लाभ का धंधा बने, इसके लिए किसानों को प्राकृतिक खेती को अपनाना होगा जिससे जहरीले रसायनों से कृषि उत्पादों को बचाया जा सके।

इस अवसर पर केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. अवधेश सिंह द्वारा बताया गया कि प्राकृतिक खेती में रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों की आवश्यकता नहीं पड़ती। मात्र एक गाय के सहारे 30 एकड़ भूमि पर प्राकृतिक खेती कर लाभ कमाया जा सकता है। वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. रूपेन्द्र सिंह द्वारा किसानों को समय से कृषितकनीकी का लाभ उठाने के लिए भारत सरकार द्वारा बनाए गए किसान सारथी से जुड़ने की सलाह दी गई। वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. करणवीर सिंह ने कृषक बंधुओं को उद्यानिकी फसलों में अपना योगदान देने के लिए जोर दिया, जिससे कि उनको आर्थिक लाभ मिल सके। वैज्ञानिक डॉ. एनएस भदौरिया ने प्राकृतिक खेती अपनाकर शुद्ध बीज उत्पादन की तकनीकी की जानकारी एवं फसल में दीमक की रोकथाम की प्राकृतिक विधि के बारे में बताया। साथ ही डॉ. बीपी एस रघुवंशी द्वारा प्राकृतिक खेती को बनाने वाले विभिन्न घटकों के बारे में कृषकों को अवगत कराया गया। कार्यक्रम में निशांत प्रभाकर स्टैनोग्राफर, दीपेन्द्र शर्मा एसआरएफ एवं प्रशांत पांडे कार्यालय अधीक्षक का सहयोग रहा, साथ ही जिले के विभिन्न गांव के दर्जनों किसानों द्वारा भाग लिया गया।

दलहन फसल का वैज्ञानिकों ने किया भ्रमण, दी सलाह

टीकमगढ़। जागत गांव हमार

गत दिवस कृषि विज्ञान केंद्र, टीकमगढ़ द्वारा किसानों के यहां समूह दलहन अग्रिम पंक्ति प्रदर्शन का खेतों पर भ्रमण किया गया है। यह भ्रमण कृषि विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख, डॉ. बीएस किरार साथ ही केंद्र के वैज्ञानिक, डॉ. एसके सिंह, डॉ. यूएस धाकड़, डॉ. एसके जाटव, डॉ. आईडी सिंह, जयपाल छिगारहा के साथ किया गया। इस प्रदर्शन का निरीक्षण राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, भोपाल से डॉ. अश्विनी टिकले, तकनीकी सहायक द्वारा किया गया। इस निरीक्षण में अश्विनी टिकले द्वारा किसानों के यहां राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन अंतर्गत समूह अग्रिम पंक्ति प्रदर्शन ग्राम दरगाह कला में किसानों के खेतों पर जाकर चना एवं मसूर के प्रदर्शन को देखा साथ ही किसानों को खेती से संबंधित जानकारी दी एवं चना में तीन पत्ती आने पर तुड़ाई के बारे में कहा यदि आप लोग चना तुड़ाई करते हैं तो उससे चने में शाखा निकलती है और उत्पादन में भी वृद्धि होती है। केंद्र के वैज्ञानिक एवं समूह दलहन प्रभारी डॉ. एसके जाटव द्वारा प्रदर्शन में दी गई चना की किस्म आरवीजी 202 जो कि उखटा रोग प्रतिरोधी है। इसका उत्पादन भी अधिक होता है। यह रोगों के लिए प्रतिरोधी है। मसूर की किस्म आईपीएल 316 को भी प्रदर्शन में दी गयी है। यह सूखे क्षेत्रों के लिए सहिष्णु होती है, इसमें कम पानी की आवश्यकता होती है।

प्राकृतिक खेती के लिए पोर्टल पर पंजीयन प्रारंभ

मंदसौर। प्राकृतिक खेती के लिए पोर्टल पर पंजीयन प्रारंभ-मध्यप्रदेश में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग द्वारा प्राकृतिक खेती करने वाले इच्छुक कृषकों के लिए पोर्टल पर पंजीयन प्रारंभ किया है। परियोजना संचालक आत्मा जिला मंदसौर द्वारा बताया गया कि जिले के किसान जो प्राकृतिक खेती करने के इच्छुक हैं, वह अपने विकासखंड के कार्यालय वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी से संपूर्ण जानकारी लेकर पंजीयन करवा सकते हैं। पंजीयन के लिए कृषक का नाम, पिता का नाम, वर्ग, ग्राम, ग्राम पंचायत, मो. नं, कुल रकबा, प्राकृतिक खेती के लिए रकबा, खसरा नंबर एवं देसी गाय की संख्या की जानकारी। अधिक जानकारी के लिए कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।

मंदसौर केवीके पर मनाया गया किसान दिवस

मंदसौर। जागत गांव हमार

कृषि विज्ञान केंद्र मंदसौर पर किसान दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। किसान दिवस सह कृषक संगोष्ठी में वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख डॉ. जीएस चुंडावत द्वारा प्राकृतिक खेती के बारे में जानकारी दी, जिसमें जीवामृत, घन जीवामृत, बीजा मृत, मल्चिंग, मिश्रित खेती तथा सिंचाई पद्धति के बारे में बताया गया कि किस प्रकार इनका उपयोग कर प्राकृतिक खेती में लागत कम किया जा सके। साथ ही साथ किसान भाइयों को भारत सरकार एवं राज्य सरकार की कृषि योजनाओं के बारे में जानकारी दी। इसके अलावा पोषक तत्व की जानकारी डॉ. रोशन गलानी, रोग प्रबंधन की जानकारी डॉ. बीके पाटीदार के द्वारा तथा खाद्य प्रसंस्करण की जानकारी डॉ. अंकित पांडे, उद्यानिकी महाविद्यालय, मन्दसौर के द्वारा प्रदान की गई। इसके साथ साथ लाइव प्रसारण के द्वारा केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा किसान भाइयों को उद्बोधन दिया गया, को किसानों को दिखाया गया। कार्यक्रम का संचालन राकेश अस्के द्वारा किया गया तथा धन्यवाद परमेश सोनी द्वारा ज्ञापित किया गया।

गांव में किसानों की फसल खरीद रही हल्दीराम-पेप्सिको

छिंदवाड़ा। चंदन गांव में संजय गुप्ता के खेत पर प्राकृतिक, जैविक तरीके से उत्पादित आलू, कुम्हड़ा (भूरा) की गुणवत्ता इतनी अच्छी रहती है कि हल्दीराम पेठा बनाने और पेप्सिको चिप्स बनाने के लिए दोनों फसल खेतों से ही अच्छे दाम पर खरीदती है। इसके अलावा जैविक तरीके से गेहूं, चना, मटर, स्ट्रॉबेरी, भिंडी, पालक, मैथी, पत्तागोभी, फूल गोभी, लहसुन, कटहल, नींबू, पपीता, बरबटी, चीकू, इमली आदि सभी प्रकार की फसल एवं फल वृक्ष की विभिन्न प्रजातियां खेतों में लगी हुई हैं। गुप्ता कुशल प्रबंधन से खेती व्यवसाय की भांति करते हैं। इनके द्वारा उत्पादित फसल हो या फल फूल गुणवत्तायुक्त होने से आसानी से अच्छे दाम पर बेचते हैं। कृषि फार्म को अनुसंधान केंद्र बनाने के अलावा जल संवर्धन की दिशा में भी खेतों में कार्य किया गया है। गुप्ता को मप्र शासन द्वारा विदेश भ्रमण यात्रा के लिए भी भेजा जा चुका है। इनकी यह सभी उपलब्धियां देखने के लिए जिले के उपसंचालक कृषि जितेंद्र कुमार सिंह, आंचलिक कृषि अनुसंधान के डॉ. विजय पराडकर, पशुपालन विभाग के डॉ. पक्षवार, सहायक संचालक धीरज ठाकुर, अनुविभागीय अधिकारी नीलकंठ पटेरिया, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी श्रद्धा डेहरिया, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी बसंती डेहरिया पहुंचीं थीं।

गडमल को जीआई टैग दिलाने में जुटा कृषि विज्ञान केंद्र बैतूल

बैतूल। जागत गांव हमार

गडमल एक क्षेत्र विशेष भीमपुर विकासखंड के कुछ आदिवासी गांव जैसे-दामजीपुरा, बटकी, डुलारिया, गोबरबेल जैसे लगभग 25 गांव के आदिवासी कृषकों के द्वारा उगाई जाने वाली अपने आप में एक नई दलहनी फसल है जिसकी देश या विश्व स्तर पर कहीं कोई वैज्ञानिक पहचान नहीं है।

यह फसल लेट खरीफ यानी सितम्बर माह में बोई जाती है, लगभग 90 दिन में पककर तैयार होती है। प्राकृतिक कारणों से खरीफ की प्रमुख फसलें फेल होने पर इसका उत्पादन लिया जा सकता है। यह दलहनी फसल आदिवासियों के द्वारा दाल के रूप में एवं इसका आटा बनाकर रोटी के रूप में उपयोग की जाती है। पीढ़ियों से यह फसल आदिवासियों के द्वारा उगाई जा रही है एवं खाने के अलावा आदिवासियों द्वारा उनके धार्मिक अनुष्ठान में भी इसका प्रयोग किया जाता है। विषाणु रोग मोजेक के प्रकोप से इसका क्षेत्रफल एवं उत्पादन कम हुआ है।

कृषि विज्ञान केन्द्र, बैतूल द्वारा इस फसल को पहचान दिलाने एवं इसके संरक्षण के लिए राष्ट्रीय पादप आनुवंषिक संसाधन ब्यूरो, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली के सहयोग से दिनांक 22 दिसम्बर 2022 को दामजीपुरा में गडमल दिवस मनाया गया। इस कार्यक्रम में डॉ. कुलदीप त्रिपाठी, वैज्ञानिक, राष्ट्रीय पादप आनुवंषिक संसाधन ब्यूरो, नई दिल्ली, कृषि विज्ञान केन्द के वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख डॉ. व्हीके वर्मा, वैज्ञानिक आरडी बारपेटे एवं डॉ. मेघा दुबे ने भाग लिया। गडमल के बीज, पौधे, फूल के नमूने लिए गए। वैज्ञानिक अध्ययन के बाद फसल को देश और विश्व के स्तर पर पहचान मिलने की संभावना है। कृषि विज्ञान केन्द्र, बैतूल द्वारा इस फसल को जिले के नाम पर जीआई टैग दिलवाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

किसान सम्मान निधि की राशि से वंचित होने पर पटवारी राधा शर्मा निलंबित

कलेक्टर ने ग्रापं अनघौरा में चौपाल लगाकर सुनीं लोगों की समस्याएं

टेंटरा में डिलेवरी के लिए सोमवार से स्टाफ नर्स होंगी तैनात

ग्रामीणों ने बताया कि इस क्षेत्र का डिलेवरी सब स्टेशन टेंटरा है, वहां स्टाफ नर्स न होने के कारण डिलेवरी के लिए महिलाएं सबलगढ़ तक पहुंचती हैं। कलेक्टर ने बीएमओ को निर्देश दिए कि तत्काल सोमवार से स्टाफ नर्स डिलेवरी के लिए तैनात की जाए, मुझे तत्काल सूचित किया जाए।

मुरैना। जागत गांव हमार

सुशासन सप्ताह के तहत कलेक्टर अंकित अस्थाना ने ग्राम पंचायत अनघौरा के पंचायत भवन पर चौपाल लगाकर ग्रामीणों की समस्याओं को सुना। कलेक्टर ने ग्रामीणों से पूछा कि राशन सभी को मिलता है, स्कूल समय पर खुलता है, पंचायत से किसी को कोई शिकायत तो नहीं, गांव में रास्ते, नालियां, आंगनवाड़ी, संबल के प्रकरण सत्यापन के लिये लंबित तो नहीं, नामान्तरण, बटवारा, सीमांकन के संबंध में किसी को कोई समस्या तो नहीं, कोई भी ग्रामीण अपनी समस्याओं को खड़े हो अवगत करा सकता है। कलेक्टर ने कहा कि जल-जीवन मिशन का कार्य शीघ्र प्रारंभ हो रहा है। जल जीवन मिशन का कार्य अच्छी क्वालिटी में पाइप लाइन डले, टंकी का कार्य सही हो। गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाये, इसमें ग्रामीणजन भी निगरानी करें। कमी आने पर तत्काल एसडीएम को और मुझे सूचित करें, गुणवत्ता में कमी नहीं होनी चाहिए। कलेक्टर ने कहा कि गांव के 10-10 लोगों की समिति बनाई जाए, जहां भी अतिक्रमण होता है, वह समिति मौके पर पहुंचकर निराकरण कराएं। ग्राम पंचायत के बुजुर्ग ने बताया कि मेरा पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा नहीं आया, पटवारी द्वारा जोड़ा भी नहीं गया है। कलेक्टर ने तत्काल पटवारी राधा शर्मा को मौके पर ही पीएम किसान सम्मान निधि में शामिल करने के निर्देश दिए। शर्मा ने बताया कि पोर्टल न चलने के कारण इनका नाम किसान सम्मान निधि में नहीं जुड़ पा रहा है।

इस पर ग्रामीणों ने विरोध जताते हुए कहा कि राधा शर्मा 8 माह से इस हलके में आई हैं, हमनें इन्हें देखा ही नहीं है। तत्कालीन पटवारी अली हसन लगातार आते रहते थे। इस पर कलेक्टर ने पटवारी राधा शर्मा को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने एवं उनकी विभागीय जांच करने के निर्देश दिए। आगामी आदेश तक उस पंचायत का पटवारी का कार्य अली हसन को करने के मौके पर निर्देश दिए हैं।

ग्रामीणों की मांग पर अगले सबलगढ़ में लगेगा मेडिकल बोर्ड

कलेक्टर ग्राम अनघौरा में ग्रामीणों के बीच चौपाल लगाकर समस्याएं सुन रहे थे, उसी समय दिव्यांग बुजुर्ग मवसिया ने कहा कि मैं विकलांग हूं, मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाने के लिए जिला मुख्यालय पर जाने के लिए कठिनाई होती है। मुझे ट्राइसकिल चाहिए। कलेक्टर ने तत्काल मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को निर्देश दिए कि अगले शुक्रवार को मेडिकल बोर्ड सबलगढ़ मुख्यालय पर लगाया जाए, ग्राम पंचायत अनघौरा के सरपंच, सचिव सभी दिव्यांग लोगों को ले जाकर मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाएं। कलेक्टर ने ग्रामीणों से कहा कि सभी के आयुष्मान कार्ड बनाए गए होंगे, उससे 5 लाख रुपए तक का ईलाज मुफ्त दिया जाता है। मौके पर वीरबल कुशवाह ने अपनी बहन के मुख्यमंत्री कन्या विवाह की राशि एवं आवास दिलाने की मांग की। कलेक्टर ने तत्काल जिला पंचायत के सीईओ को निर्देश दिए कि मुख्यमंत्री आवास प्लस में नाम शामिल करें और मुख्यमंत्री कन्या विवाह की राशि पात्रता होने पर जारी करें। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि मुरली मनोहर मंदिर का जीर्णोद्वार किया जाए, इस संबंध में एसडीएम मेघा तिवारी को प्रकरण तैयार करने के निर्देश दिए।

क्षेत्र में भ्रमण के समय जिला सदस्यों को भी सूचित करें

विकास कार्यों की प्रगति से जिपं सदस्यों को भी अकगत कराएंः गुर्जर

मुरैना। जागत गांव हमार

जिला पंचायत मुरैना की अध्यक्ष आरती गुर्जर ने कहा है कि अधिकारी जिले में चल रहे विकास कार्यों की वस्तुस्थिति से जिपं सदस्यों को भी अवगत कराएं, ताकि जनप्रतिनिधि मौके पर पहुंचकर चल रहे निर्माण कार्यों को अपने संज्ञान में रखें। नियमित निरीक्षण से विकास कार्यों में गुणवत्ता अच्छी बनी रहेगी। विभागीय अधिकारी जिस क्षेत्र में भ्रमण पर निकलें, उससे से पहले संबंधित क्षेत्र के जिपं सदस्यों को भी सूचित करें, ताकि वहां पहुंचकर अधिकारियों के साथ निर्माण कार्यों का अवलोकन करते हुए कमियों को दूर कराया जा सके। यह निर्देश उन्होंने जिला पंचायत की सामान्य सभा की बैठक में दिए। इस अवसर पर जिपं उपाध्यक्ष बनवारी लाल धाकड़, जिपं सीईओ डॉ. इच्छित गढ़पाले, जिपं के अतिरिक्त सीईओ आरके गोस्वामी, सहित अंबाह, दिमनी, मुरैना, जौरा विधायक प्रतिनिधि मौजूद थे। जिपं अध्यक्ष गने कहा कि जिला पंचायत की सामान्य सभा की बैठक में प्रमुखतः महिला बाल विकास, नरेगा, 15वें वित्त आयोग, पीएचई, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं कृषि के संबंध में अधिकारियों के कार्यो की समीक्षा की गई।

ग्राम पंचायत धौंधा-कन्हार में टंकी का कार्य पूर्व कराएं

जिला पंचायत की अध्यक्षा ने कहा कि महिला बाल विकास विभाग द्वारा चल रहीं योजनाएं एवं अपूर्ण पदों को शीघ्र भरने की कार्रवाई कराएं, जो आंगनवाड़ी भवनविहीन हैं, उनके भवन निर्माण शीघ्र प्रारंभ कराए जाएं। उन्होंने कहा कि क्षेत्रों में सीडीपीओ, सुपरवाइजर, भ्रमण के समय जाएं तो जनप्रतिनिधियों को भी सूचित करें। जिला पंचायत अध्यक्ष ने कहा कि पहाडगढ़ विकासखंड की ग्राम पंचायत धौंधा-कन्हार में टंकी का कार्य पूर्णतः की ओर है, उन्हें हैंडओव्हर कराएं और रविवार को ईपीएचई धौंधा-कन्हार पहुंचकर जिला पंचायत सदस्य को साथ में लेकर अवलोकन करें। इसके साथ ही उन्होंने स्कूल शिक्षा विभाग की समीक्षा की। समीक्षा के दौरान बताया कि जिले में 101 अनुदान प्राप्त शालाएं हैं, जिनमें जो शिक्षक सेवानिवृत्त हो चुके हैं, उन शालाओं में शिक्षकों की व्यवस्था की जाएं। इसके साथ ही 79 नवीन शाला खोलने का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। उसे परसू अवश्य करें। उन्होंने कहा कि स्कूलों में मध्यान्ह भोजन मीनू के अनुसार मिले, समय-समय पर स्कूलों का निरीक्षण होता रहे, ताकि मध्यान्ह भोजन भी अच्छा एवं क्वालिटी का मिलता रहे। अध्यक्षा ने कहा कि सीएम की प्राथमिकता वाली मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत इस वर्ष जिले में एक भी शादियां नहीं हुई है, इसके लिए प्रेरित करें।

14 मुर्रा पाड़ो का मुरैना जिले के पशुपालकों को किया गया वितरण

मुरैना। सुशासन सप्ताह के तहत समुन्नत मुर्रा पाडा योजनांतर्गत वर्ष 2021-22, 2022-23 के 14 मुर्रा पाड़ो को मुरैना जिले के पशुपालकों को वितरित किए गए। इस योजना का उद्देश्य देशी भैंसों का नस्ल सुधार करना है। जिसमें पशुपालन विभाग की तरफ से 75 प्रतिशत राशि अनुदान के रूप में प्रदान की गयी एवं शेष 25 प्रतिशत राशि अंशदान के रूप में हितग्राहियों के द्वारा दी गयी। इस वितरण अवसर पर पशुपालन एवं डेयरी विभाग मुरैना के उपसंचालक डॉ. आरपीएस भदौरिया उपस्थित थे।

किसान भाई प्राकृतिक खेती करेंः तोमर

मुरैना। जागत गांव हमार

कृषि विज्ञान केन्द्र मुरैना में हिल (इण्डिया) लिमिडेट नई दिल्ली द्वारा कृषि में रसायनों का समुचित उपयोग एवं प्राकृतिक खेती विषय पर गुरूवार को किसान संगोष्ठी का आयोजन किया गया। किसान संगोष्ठी में मुख्य अतिथि के रूप में निदेशक किसान ट्रस्ट इफको, नई दिल्ली अरूण सिंह तोमर ने किसानों से प्राकृतिक खेती एवं कृषि में रसायनों का समुचित एवं विवेक पूर्ण उपयोग करने की सलाह दी। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए निदेशक विस्तार सेवाएं, राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विवि, ग्वालियर डॉ. वायपी सिंह ने किसानों से रसायनों का दक्षतापूर्ण उपयोग एवं प्रकृतिक खेती के लाभों के बारे में विस्तार से बताया। निदेशक अनुसंधान सेवाएं राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विवि ग्वालियर डॉ. संजय शर्मा ने मिट्टी परीक्षण कराकर उर्वरकों का उपयोग करने की सलाह दी। कार्यक्रम में हिल (इण्डिया) लिमिटेड के जनरल मैनेजर डॉ. राजेन्द्र थापर ने अनुशंसित मात्रा में रसायनों का उपयोग करने की सलाह दी। कार्यक्रम में कृषि विज्ञान केन्द्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख डॉ. राजपाल सिंह तोमर ने प्राकृतिक खेती अपनाकर स्वस्थ रहने की सलाह दी। संगोष्ठी में सह संचालक अनुसंधान डॉ. एसएस तोमर ने संरक्षित खेती करने की सलाह दी। संगोष्ठी में जितेन्द्र नारायण, ओमप्रकाश लहारिया निदेशक सीएएमसीओ लिमिटेड, कृषि विज्ञान केन्द्र के वैज्ञानिक डॉ. सुखवीर सिंह चौहान, डॉ. रीता मिश्रा, डॉ. अशोक सिंह यादव, डॉ. ब्रजराज सिंह कसाना, डॉ. स्वाति सिंह तोमर, अर्चना खरे, उप संचालक, पशुपालन, उप संचालक कृषि एवं जिले के 520 प्रगतिशील कृषकों ने भाग लेकर कृषि की जानकारी प्राप्त की। कार्यक्रम का संचालक डॉ. अशोक सिंह यादव और आभार व्यक्त डॉ. सुखवीर सिंह चैहान ने किया।

जागत गांव हमार के सुधि पाठकों...

» जागत गांव हमार कृषि, पंचायत और ग्रामीण विकास आधारित समाचार पत्र है, जिसके लिए आपका स्नेह और प्यार हमें शुरू से मिलता रहा है। हम आशा और विश्वास करते हैं कि आगे भी मिलता रहेगा।

» समाचार पत्र के लिए विशेषज्ञों की राय, प्रकाशन योग्य सामग्री के साथ-साथ आपके समक्ष इसे पहुंचाने तक हमारी जिम्मेदारी बड़ी चुनौतीपूर्ण है। आपके सहयोग से ही हम इस चुनौती का सामना कर पाएंगे।

» ऐसे में हमारी आपसे अपेक्षा और आग्रह है कि जागत गांव हमार के वार्षिक सदस्य बनें और इसके लिए नीचे लिखे गए नंबर पर संपर्क करें।

संपर्क करें- अजय द्विवेदी-9229497393, 94250485889

"आपका सहयोग हमारी मजबूती का आधार बनेगा"

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक अजय कुमार द्विवेदी द्वारा जय माता प्रिंटर्स, मं.नं.1, पेमदीपुरा बापू कालोनी के पास चिकलोद रोड, जहांगीराबाद, भोपाल(मप्र) से मुद्रित एवं एमआईजी 30, शिवकल्प, अयोध्या बाईपास भोपाल, मप्र से प्रकाशित। संपादकः अजय कुमार द्विवेदी, स्थानीय संपादक- **अरविंद मिश्र, संपर्क** -9229497393, 9425048589, ईमेलः- jagatgaon.bpl@gmail.com (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल होगा)